

ग्रीष्मकालीन भिंडी उत्पादन की उन्नत तकनीक

ग्रीष्मकालीन सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है। ग्रीष्मकाल में भिंडी की अंगेती फसल लगाकर किसान भाई अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। मुख्य रूप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खनिज लवणों के अतिरिक्त विटामिन 'ए', 'सी' थाईमीन एवं रिबोफ्लेविन भी पाया जाता है। भिंडी के फल में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। भिंडी का फल कब्ज रोगी के लिए विशेष गुणकारी होता है। इस लेख में ग्रीष्मकालीन भिंडी की उत्पादन तकनीक की विवेचना की गयी है:-

जलवायु एवं भूमि की तैयारी:- भिंडी के उत्पादन हेतु गर्म मौसम अनुकूल होता है। बीजों के अंकुरण हेतु 20 सेंटीग्रेड से कम का तापमान प्रतिकूल होता है। 42 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर फूल का पराग नहीं होता है एवं फूल गिर जाते हैं।

सामान्यतः भिंडी की खेती सभी प्रकार की भूमियों पर की जा सकती है परन्तु हल्की दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश उपलब्ध हो एवं उचित जल निकास की सुविधा हो, भिंडी की खेती हेतु श्रेष्ठ होती है। भूमि की दो-तीन बार जुताई कर भूरभूरा कर तथा पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए।

उन्नत किस्में- अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभणी क्रांति, पूसा-ए-4, वर्षा उपहार, बीज एवं बीजोपचार:- ग्रीष्मकालीन फसल हेतु 18-

20 कि.ग्रा. बीज एक हेक्टर बुवाई के लिए पर्याप्त होता है जबकि वर्षाकालीन फसल में अधिक बढ़वार की कारण 12-15 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टर उपयोग करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन भिंडी के बीजों को बुवाई के पूर्व 12-24 घंटे तक पानी में डुबाकर रखने से अच्छे अंकुरण होता है। बुवाई के पूर्व भिंडी के बीजों को 3 ग्राम थायरम या कार्बेन्डाजिम प्रति किलो बीजदर से उपचारित करना चाहिए। संकर किस्मों के लिए 5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर की बीजदर पर्याप्त होती है।

बुवाई- ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई फरवरी-मार्च में की जाती है। फिर भी अंगेती फसल हेतु छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 15 जनवरी के बाद भी बुवाई की जा सकती है। यदि भिंडी की फसल लगातार लेनी है तो तीन सप्ताह के अंतराल पर फरवरी से जुलाई के मध्य अलग-अलग खेतों में भिंडी की बुवाई की जा सकती है।

ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार दूरी 25-30 सें.मी. एवं कतार में पौधे की मध्य दूरी 15-20 सें.मी. रखनी चाहिए। वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार दूरी 40-45

सें.मी. एवं कतारों में पौधे की बीच 25-30 सें.मी. का अंतर रखना उचित रहता है।

पोषण प्रबंधन:- भिंडी की बुवाई के दो सप्ताह पूर्व 250-300 कि.ग्रा. सड़क हुआ गोबर खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। प्रमुख तत्वों में नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश क्रमशः 60 कि.ग्रा., 30 कि.ग्रा. एवं 50 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर की दर से मिट्टी में देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के पूर्व भूमि में देना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को दो भागों में 30-40 दिनों के अंतराल पर देना चाहिए।

जलप्रबंधन:- यदि भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो बुवाई के पूर्व एक सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में प्रत्येक पांच से सात दिन के अंतराल पर सिंचाई आवश्यक होती है। बरसात में आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए तथा अतिवृष्टि के समय उचित जलनिकास प्रबंध करना चाहिए।

निर्दाई-गुड़ाई:- नियमित निर्दाई-गुड़ाई कर खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। बोने के 15-20 दिन बाद प्रथम निर्दाई-गुड़ाई करना जरूरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु रासायनिक निर्दानाशकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बासालिन को 1.2 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टर की दर से पर्याप्त नम खेत में बीज बोने के पूर्व मिलाते से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।

फल की तोड़ाई एवं उपज:- किस्म की गुणता के अनुसार 45-60 दिनों में फलों की तोड़ाई प्रारंभ की जाती है एवं 4 से 5 दिनों के अंतराल पर नियमित तोड़ाई की जानी चाहिए। ग्रीष्मकालीन भिंडी फसल में उत्पादन 60-



7 0 किंटल प्रति हेक्टर तक होता है।

7 0

किंटल प्रति हेक्टर तक होता है।

पौध संरक्षण:-

भिंडी के प्रमुख रोग

पीत शिरा मौजक एवं चूर्णिल

आसिता एवं नुकसानदायक कीट

प्ररोह एवं फल छेदक तथा जैसिड है।

पीत शिरा रोग:- यह भिंडी की फसल में नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख रोग है। इस रोग के प्रकोप से सर्वप्रथम पत्तियों की शिराएं पीली पड़ने लगती हैं। तत्पश्चात् पूरी पत्तियाँ एवं फल भी पीले रंग के हो जाते हैं पौधे की बढ़वार रुक जाती है। वर्षा ऋतु में इस रोग का संक्रमण अधिक होता है।

सर्वप्रथम इस रोग के लक्षण वाले पौधे दिखाई देते ही उन्हें उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। यह विषाणु जनित रोग सफेद मक्खी कीट द्वारा स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। अतः रोग संवाहक कीट के नियंत्रण हेतु आवसी मिथाइल डेमेटान 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से रोग का प्रसारण कम होता है। पीतशिरा रोग प्रतिरोधी किस्मों जैसे अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभणी क्रांति इत्यादि का चुनाव करना चाहिए। फसल के चारों ओर 2-3 कतार मक्का बोने से भी रोग का फैलाव नियंत्रित किया जा सकता है।

चूर्णिल आसिता:- इस रोग में भिंडी की पुरानी निचली पत्तियों पर सफेद चूर्ण युक्त हल्के पीले धब्बे पड़ने लगते हैं। ये सफेद चूर्ण वाले धब्बे काफी तेजी से फैलते हैं। इस रोग का नियंत्रण न करने पर पैदावार 30 प्रतिशत तक

कम हो सकती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु

घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 या 3 बार 12-15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए।

प्ररोह एवं फल छेदक:- इस कीट का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्था में इल्ली कोमल तने में छेद करती है जिससे तना सूख जाता है। फूलों पर इसके आक्रमण से फल लगाने के पूर्व फूल गिर जाते हैं। फल लगने पर इल्ली छेदकर उनको खाती है जिससे फल मुड़ जाते हैं एवं खाने योग्य नहीं रहते हैं।

जैसिड:- ये सुक्ष्म आकार के कीट पत्तियों, कोमल तने एवं फल से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं।

फल छेदक के द्वारा आक्रमण किये गये फलों एवं तने को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। क्रिऑलफास 25 ई.सी. 1.5 मिली लीटर या इंडोसल्फान 1.5 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से कीट प्रकोप की मात्रा के अनुसार 2-3 बार छिड़काव करने से जैसिड एवं फल प्ररोह छेदक कीटों का प्रभावी नियंत्रण होता है। फल बनने के उपरांत कीट प्रकोप होने पर 'फेनवेलरेट' 0.5 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर उपर्युक्त बनाये कीटनाशक के साथ अदल-बदल कर प्रयोग करें।

कैसे करें संरक्षित खेती

संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य सब्जी फसलों को मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। इसमें फसल को किसी एक कारक या कई कारकों से बचाकर उगाया जा सकता है।

संरक्षित सब्जी उत्पादन के लिए सब्जी उत्पादकों को संरक्षित खेती व विभिन्न संरक्षित संरचनाओं की पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही उत्पादक तय कर सकता है कि वह किस प्रकार की संरक्षित तकनीक अपनाकर बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करे। कौन कौन सी संरक्षित प्रौद्योगिकियाँ हैं जिनमें वह सब्जियों को वर्ष भर उगा सकता है। संरक्षित संरचनाओं को बनाने के बाद में रख रखाव में क्या व्यय होगा तथा उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों को वह किस बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमा सकता है। इन सभी विषयों की जानकारी आवश्यक है।

मुख्यतः सब्जी उत्पादन हेतु उचित व उपयुक्त संरक्षित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करती है। लेकिन इसके अलावा किसान की आर्थिक दशा, टिकाऊ व उच्च बाजारकी उपलब्धता व बिजली की उपलब्धता आदि कारक भी इसको निर्धारित करते हैं। सब्जियों के बेमौसमी उत्पादन हेतु मुख्यतः वातावरण अनुकूलित ग्रीनहाउस, प्राकृतिक वायु संचारित ग्रीनहाउस, कम लागत वाले पॉलीहाउस, वाक-इन-टनल, कोट अवरोधी नेटहाउस तथा लो प्लास्टिक टनल आदि संरचनाओं का उपयोग किया जाता है।

बेमौसमी सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए सब्जियों की पौध प्लग ट्रे पद्धति से ग्रीनहाउस में तैयार की जाती है। तथा उसके बाद पौधों को उपयुक्त संरक्षित संरचना में रोपाई करते हैं।

वाक-इन-टनल तकनीक

वाक-इन-टनल एक प्रकार की अस्थायी संरक्षित संरचना है जो आधा इंच मोटाई के जंग रोधी पाईपों को अर्धगोलाकार आकार में मोड़कर तथा इन्हे सरियों के टुकड़ों के सहारे खेत में खड़ा करके उसके



की संरक्षित संरचनाओं में दिन के समय जब सूर्य की रोशनी प्लास्टिक पर मंडती है तो टनल के अन्दर का तापमान काफी (लगभग 10 से 12 डि.ग्री से.) बढ़ जाता है। जिससे कच्चे वगीय सब्जियों को कम तापमान के दिनों में भी बढ़वा कर देने में सफलता मिल जाती है।

वाक-इन-टनल की लम्बाई आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सामान्यतः इनकी लम्बाई 25 से 30 मीटर होती है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं- प्लास्टिक की चादर की उपलब्ध माप, टनल में हवा का आदान प्रदान, तथा इस लम्बाई के टनल में मधुमक्खियों को भी परागण कार्य करने में कोई असुविधा नहीं होती। इन संरचनाओं को बनाने में लागत भी बहुत कम ही आती है। तथा अस्थायी होने के कारण इनकी देखभाल भी सरलता पूर्वक की जा सकती है।

इन संरचनाओं का उपयोग केवल सर्दी के मौसम (दिसम्बर जनवरी व फरवरी माह) में ही फसल उत्पादन के लिए किया जा सकता है। क्योंकि सर्दी के बाद इसके अंदर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा हवा का अधिक आदान प्रदान न होने के कारण तब इनमें फसल उगाना संभव नहीं होता है। यही नहीं इनका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में और भी लम्बे समय तक सब्जी उत्पादन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार इन संरचनाओं को ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी सब्जी उत्पादन के लिए उपयोग में लाना संभव है।

छतरपुर के गांधी आश्रम में जैविक खेती का अद्भुत प्रयोग



यहां जैविक, परंपरागत और टिकाऊ खेती की किताबी बातें नहीं की जाती बल्कि जमीन पर नजर भी आती हैं। कड़कड़ाती ठंड और पाला भी इस इलाके में लगी दलहनी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पेड़-पौधों की रंगत देखकर ही लगता है कि यहां की मिट्टी ने अपनी खोयी ताकत और ऊर्जा फिर पा ली है। यह कोई वर्षों की मेहनत नहीं बल्कि केवल चार साल की लगन का नतीजा है। मिसाल पेश करने वाले हैं - संजय और दमयंती। जिस बुदेलखंड में पिछले पांच सालों में भयंकर सूखे से किसानों की कमर टूट गई है, उसी धरती पर एक जगह ऐसी भी है, जहां खुशियों की खेती लहलहा रही है। विदर्भ के बाद मध्यप्रदेश में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं के बीच खेती का यह प्रयोग एक मिसाल पेश करता है। यहां जैविक, परंपरागत और टिकाऊ खेती की किताबी बातें नहीं की जाती बल्कि जमीन पर नजर भी आती हैं। कड़कड़ाती ठंड और पाला भी इस इलाके में लगी दलहनी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पेड़-पौधों की रंगत देखकर ही लगता है कि यहां की मिट्टी ने अपनी खोयी ताकत और ऊर्जा फिर पा ली है। यह कोई वर्षों की मेहनत नहीं बल्कि केवल चार साल की लगन का नतीजा है। मिसाल पेश करने वाले हैं संजय और दमयंती और जगह है छतरपुर।

टिकाऊ खेती की बात से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी होगा। गांधी आश्रम छतरपुर ऐतिहासिक महत्व की जगह है। अंग्रेजी शासन काल के बाद दीवान साहब के बंगले से यह जगह गांधी विचारों को आगे ले जाने का एक केंद्र बनी। तत्कालीन दीवान ने विनोबा के भूदान आंदोलन से प्रेरित होकर इस बंगले और बंगले से लगी जमीन को गांधी विचारों के लिए समर्पित कर दिया। उसके बाद इसे गांधी आश्रम के नाम से विकसित किया गया। सांस्कृतिक-साहित्यिक-सामाजिक गतिविधियों को यहां से संचालित किया जाता रहा। सत्तर के दशक में जब चंबल में डकुओं का आतंक अपने चरम पर पहुंचकर आत्मसमर्पण की ओर बढ़ा तब इस प्रक्रिया की बुनियाद इसी आश्रम के पुस्तकालय से पड़ी। जयप्रकाश नारायण के साथ यहां डकुओं की बातचीत हुई और इसके बाद डकुओं

ने आत्मसमर्पण भी किए। गांधी का ग्रामस्वराज, बुनियादी तालीम और टिकाऊ विकास की अवधारणाओं को झलक इस छोटे से आश्रम में दिखाई देती है। बीच में एक लंबा दौर ऐसा भी आया जब यह आश्रम भूमिफियों और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र में तब्दील हो गया।

2006 में गांधी विचारों से जुड़े संजय और दमयंती जब इस जगह आए तो उन्होंने ठान लिया कि यहां की तस्वीर को बदलने के लिए वह कठिन परिश्रम करेंगे। खेती-किसानी और प्रकृति प्रेमी भाई ने इस आश्रम से लगे लगभग चालीस



एकड़ खेत में जैविक खेती के प्रयोग को शुरू करने की योजना बनाई। एक ओर जहां नकद फसलों ने फसलों की विविधता को खत्म कर दिया है वहीं इस आश्रम में उन्होंने अलग-अलग फसलों को अपनाया। इस छोटी सी जमीन पर गेहूं, चना, सरसों, अरहर, ज्वार, मक्का, जौ सहित ऐसी फसलें लीं जो सीधे-सीधे किसान अपने खाने के लिए भी उपयोग करते हैं। दरअसल खेती का परंपरागत तरीका था

भी यहीं कि किसान ज्यादातर खाद्यान्न और मसाले अपने खेतों में पैदा किया करते थे और उन्हें हर चीज के लिए बाजार की ओर मुंह नहीं देखा पड़ता था, अब किसान गेहूं-सोयाबीन पैदा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन दाल-मसालों के लिए वह बाजार पर निर्भर है। खेती की इस विविधता से आश्रम की व्यवस्थाएं भी स्वतः संचालित होती हैं। यहां तक की सब्जी और फलों का उत्पादन भी आश्रम से ही हो जाता है। इस खेती की सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले चार सालों से यहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। वर्मी कम्पोस्ट और गोमूत्र के जरिए यहां की फसलों को जान मिलती है। 40 एकड़ के इस क्षेत्र को आश्रम के केवल सात कार्यकर्ता अंजाम देते हैं। संजय भाई बताते हैं कि आज के इस दौर में जैविक खेती करना थोड़ा कठिन जरूर लग सकता है पर यह असंभव कतई नहीं है। हम अपने खेतों में उतना ही समय खर्च करते हैं जितना दूसरे किसान। पर यहां आपको यह समझना होगा कि जमीन क्या चाहती है। किस तरह की जमीन पर किस तरह के फसल ठीक रहेगी यह समझना होगा। इस आश्रम की एक खास बात यह है कि आप यहां पूरी तरह जैविक भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहां तक की दाल-मसाले और तेल भी खुद की उगाई गई तिल का। इस आश्रम में चल रही खेती के प्रयोग को समझने फ्रांस के निकोलस आए हैं। निकोलस कहते हैं कि 'वह भारत में जैविक खेती के अलग-अलग प्रयोगों को उन्होंने देखा, लेकिन यह प्रयोग सबसे अद्भुत है। इसलिए भी क्योंकि यह गांधी के विचारों से जुड़ा हुआ है। गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे और गांव की अर्थव्यवस्था के एक मॉडल की बात करते थे जहां कि ग्रामवासी आपसी व्यवहार में अपने साझा जीवन को अंजाम देते थे। यह प्रयोग अपने आप में दिलचस्प है।' यही कारण है कि वह न केवल इस खेती पर अध्ययन कर रहे हैं बल्कि इस प्रयोग के साथ इतना रम गए हैं कि वह खुद खेतों में पसीना बहाते हैं। बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता भावेश भी इस प्रयोग के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि कम लागत की इस खेती को जीवन के साथ जोड़कर भी देखा जाना जरूरी है।

BRIEF NEWS

शेख शहीद भिखारी व शहीद टिकैत सिंह समारोह समिति का चुनाव संपन्न

RANCHI : आईएसएम चौक पुंदाग रांची में शेख भिखारी शहीद टिकैत उमराव सिंह समारोह समिति की बैठक नेजामुद्दीन मस्तान बाबा की अध्यक्षता में हुआ इस दौरान समिति का चुनाव किया गया। इसमें मुख्य संरक्षक एजाज अंसारी, इरफान अहमद, आफताब हुसैन, सज्जाद अंसारी, शोएब आलम, अध्यक्ष तौकीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष मजहर हुसैन और इस्तिवाक अंसारी, वरीय उपाध्यक्ष कुतुब अंसारी, उपाध्यक्ष एनामुल हक, प्रधान महासचिव बिंदे मुंडा, महासचिव जुल्फाम अंसारी और इनायत हुसैन, सचिव आफरोज अंसारी और मुस्तफा अंसारी, उप सचिव शमशाद हुसैन, कोषाध्यक्ष मोविन अंसारी और मीडिया प्रभारी तौसीफ खान और गुलजा अहमद को चुने गए। समिति की ओर से 08 जनवरी 2024 को राज्य के वीर सपूत शेख शहीद भिखारी एवं शहीद उमराव टिकैत सिंह की शहादत दिवस की अवसर पर कच्वाली का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मीडिया प्रभारी तौसीफ खान ने दी।

निगम के चार वार्डों में 36 आवेदनों का हुआ निपटारा

RANCHI : आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को रांची नगर निगम की ओर से चार वार्डों में शिविर लगाया गया। इनमें वार्ड नंबर 47, 48, 49 और 50 में कुल 36 आवेदनों का निपटारा ऑन स्पॉट किया गया। इसके अलावा चारों वार्डों में जरूरतमंदों के बीच कुल 631 कंबल का वितरण भी किया गया। अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि शिविर में होल्डिंग, ट्रेड, जन्म-मृत्यु निबंधन, जल कर भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन लिया गया। सभी शहरवासी निगम स्तर के सेवाओं का लाभ इन शिविरों में आ कर ले सकते हैं।

कांके प्रखंड महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस का सम्मेलन संपन्न

RANCHI : कांके प्रखण्ड महिला कांग्रेस समिति और युवा कांग्रेस का सम्मेलन ग्राम मरवा में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय उपस्थित हुए। महिला एवं युवा कांग्रेस के पंचायत अध्यक्षों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने एवं जल्द से जल्द वृथ स्तर तक कमिटी फाइनल करने को लेकर सुबोध कांत सहाय ने टास्क दिया। इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव सुरेश कुमार बैठा, रांची महानगर अध्यक्ष जमील अख्तर, खिजरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुन्दरी तिकी, मैरी तिकी, एसटी मोर्चा के शिवदहल नायक, कांके विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मो. खालिद सैफुल्लाह, लाला महली, रती महली, महिला प्रखण्ड अध्यक्ष संजु देवी, मुस्ताक अंसारी, अफजल अंसारी, रिजवान अंसारी, दीपक साहू, नीरज यादव, हैयात अंसारी कांके प्रखण्ड के महिला एवं युवा कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष एवं पंचायत अध्यक्ष एवं भारी संख्या में महिला एवम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्टेबल रैंक में चार हजार रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही तेज

RANCHI : झारखंड पुलिस की ओर से कार्टेबल रैंक में लगभग चार हजार रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही तेज कर दी गयी है। इसे लेकर शुक्रवार को डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा की। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रिक्त पद भरने से उन्नत संगठनों, संगठित आपराधिक गिरोहों, साहज्य अपराधियों पर चौरफा कार्यवाही के साथ अन्य आपातकालीन सेवाएं, विधि-व्यवस्था संभरण, महिलाओं के विरुद्ध और अन्य सभी प्रकार के अपराधों पर रोकथाम के लिए और प्रभावी एवं सार्थक कार्यवाही करने में आसानी होगी।

atom美 ATOM INDIA RANCHI TEAM WARRIOR CENTRE 4th Floor, Shop No. 33, 33-34 Reshpa Reshpa Tower, Main Road, Ranchi - 834001 Mob. 9334435776

हाईकोर्ट ने नीरज सिंह हत्याकांड मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब

संजीव को क्यों नहीं भेजा गया एम्स

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।



देवघर में तालाब की जमीन पर अस्पताल बनाए जाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट में देवघर के मधुपुर अनुमंडल में गैर मजसूदा जमीन पर बने तालाब पर अस्पताल बनाए जाने के टेंडर को चुनौती देने वाली अरुण शाही की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में यथा स्थिति (स्टेटस को) बनाए रखने का आदेश दिया है यानी अब वहां की स्थिति पूर्व में जैसी थी वैसी कोर्ट के आले आदेश तक बनी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है। पूर्व में खंडपीठ ने अरुण शाही की रिट याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदला था। दरअसल, याचिकाकर्ता का कहना है कि देवघर के गोविंदपुर मोजा में मधुपुर अनुमंडल स्थित बांध/तालाब पर अस्पताल बन रहा है। इसका शिलान्यास 18 सितंबर को चुका है। तालाब को भरकर उसकी जमीन पर अस्पताल बनाना गलत है।

जेल प्रशासन अगस्त माह से ही इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है। पूर्व में हाईकोर्ट दो बार संजीव सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। नीरज की हत्या के

HC ने अवैध खनन मामले में सुनील यादव की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपित सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका की ऑफिश सुनवाई शुक्रवार हुई। मामले में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई जनवरी माह में होगी। याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वह निराधार हैं। अवैध खनन मामले में उनकी कोई सलिपता नहीं है। सुनील यादव के ओर से हाई कोर्ट में अधिवक्ता सव्यसाची ने पक्ष रखा। गत सात अक्टूबर को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनील, दहू यादव का भाई है। ईडी कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपित सुनील का भाई दाहू यादव अब तक फरार है।

नगर निकाय चुनाव नहीं कराने पर पूर्व पार्षद ने हाईकोर्ट में दाखिल की अमानना याचिका

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव राज्य सरकार द्वारा नहीं कराये जाने को लेकर रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलको ने अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी सरकार आधी-अधुरी बात के साथ जनता के साथ कोर्ट का समय भी बर्बाद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है। सरकार कह रही है कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय/पंचायत चुनाव कराए जाएंगे लेकिन संविधान का प्रावधान है कि यदि ट्रिपल टेस्ट लंबे समय तक नहीं कराया गया है तो निकाय चुनाव को लॉबत नहीं रखा जाना चाहिए।

उपायुक्त ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण



ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण करते उपायुक्त। • फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI :

हर हाल में पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक सुमन को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन विभाग को भेजने को कहा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम प्रदर्शन मतदाताओं को जागरूक किए जाने के लिए निर्धारित संख्या में मशीनों निकाल कर अलग स्टूंग रूम में रखी गईं। वेयर हाउस में मशीनें निकाले जाने के दौरान सम्बंधित पदाधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल, 2017 से जेल में बंद हैं। इससे पूर्व भी हाईकोर्ट से संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।

सांसदों के निलंबन को लेकर INDIA गटबंधन ने निकाला विरोध मार्च

PHOTON NEWS RANCHI :

लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों को निलंबित करने के विरोध में आईएनडीआई गटबंधन ने शुक्रवार को रांची के जिला स्कूल से राजभवन तक विरोध मार्च निकाला।



विरोध मार्च में शामिल गटबंधन के लोग। • फोटोन न्यूज

मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लोकसभा में सांसदों के आवाज को दबा दिया गया। इसलिए हम सड़क पर आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सड़क पर प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। देश के लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं है। भाकपा के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार अडानी अंबानी के इशारे पर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार को संविधान से कोई लेना-देना नहीं, इसलिए लगातार जन विरोधी

फैसले ले रही है। आने वाले दिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश में आपातकाल की स्थिति है। केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों को निशाना बना रही है। कभी ईडी के नाम पर तो कभी सीबीआई के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस अवसर पर वित्त मंत्री

रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जनता दल के सभा को राष्ट्रीय जनता दल के रंजन यादव, धर्मेश महतो, आम आदमी पार्टी के हरी सिंह, तुणमूल के फिलोमिन टोपनो, झामुमो के जिला अध्यक्ष मुस्ताक आलम, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश किरण, सीपीआई के अजय सिंह, झामुमो के जिला सचिव हेमलाल महतो सहित कई नेता मौजूद थे।

हत्या के तीन आरोपी दोषी करार, फैसला तीन को

PHOTON NEWS RANCHI :

अपर न्यायायुक्त एसएम सज्जाद की अदालत ने शुक्रवार को रातू निवासी अम्मार अंसारी की हत्या के तीन आरोपियों मो. तौकीर खान, छोटू खान और मो. इसराफिल को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर तीन जनवरी को सुनवाई होगी। मामले में प्रभारी लोक अभियोजक मिनाक्षी कंडुलना ने अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किये जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया।



उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

मामला वर्ष 2018 का है। इस संबंध में रातू थाना में मृतक के पिता ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दो अभियुक्तों मो. तौकीर खान और छोटू खान को घटना के बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, उसी समय से दोनों जेल में हैं जबकि मो. इसराफिल बेल पर है। दोषी करार दिये जाने के बाद अदालत ने उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया।

व्या है मामला : 29 दिसम्बर, 2018 की शाम सात बजे अम्मार अंसारी की चाय पीने की बात बोलकर मो. तौकीर खान अपने साथ ले गया। दूसरी दिन यानी 10 दिसम्बर को अम्मार अंसारी का शव सिमलिया के हाजी चौक पर मिला। पुलिस ने मृतक के दोस्त तौकीर को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि वह और उसके दो दोस्तों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी निशानदेही पर छोटू खान तथा मो. इसराफिल को गिरफ्तार किया गया। तीनों को जेल भेज दिया गया था।

पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा ने ईडी कोर्ट में दायर किया डिस्चार्ज पिटीशन

PHOTON NEWS RANCHI :

ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा की ओर से शुक्रवार को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो जनवरी की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में उनके खिलाफ आरोप गठन भी होना है। पिछले दिनों हाईकोर्ट से कृष्णा साहा को जमानत मिल चुकी है। बोते पांच जुलाई को 10 घंटे की

पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉडिंग के तहत मामले की जांच कर रही है। ईडी ने कृष्णा के ठिकाने पर जुलाई 2022 में छापेमारी की थी। मामले में साहिबगंज जिले के बड़हरवा निवासी कृष्णा को मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी बताया जाता है। कृष्णा के अवैध पत्थर खदान में दो मजदूरों की दुर्घटना में मौत हो गई थी।

सचिवालय सेवा के दो अधिकारियों पर अलग अलग मामलों में होगी विभागीय कार्यवाही

RANCHI : झारखंड सचिवालय सेवा के दो पदाधिकारियों पर अलग-अलग मामलों में विभागीय कार्यवाही होगी। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इसकी स्वीकृति दे दी है। गृह, कारा विभाग के अंतर्गत कारा निरीक्षणालय में अधिसूचित व कृषि विभाग के अवर सचिव लालिमा डाडेल पर बिना किसी अनुमति या सूचित किए बिना कार्यालय में लंबी अवधि से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप हैं। जांच में प्रथम दृष्टया प्रमाणित भी पाया गया। विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और सेवानिवृत्त आइएसएस पदाधिकारी रमाकांत सिंह को जांच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया है। इसी तरह तत्कालीन अवर सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग व सम्प्रति अवर सचिव कर्मचारी चयन आयोग संतोष कुमार पर भी विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया गया है।

श्रीनाथ विश्वविद्यालय में 'तीन दिवसीय सातवां अंतरराष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव'

छात्रों का साहित्यकारों से संवाद जरूरी : रविशंकर शुक्ला

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR :

श्रीनाथ विश्वविद्यालय में 'तीन दिवसीय सातवां अंतरराष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव' का शुक्रवार को दूसरा दिन था। इस अवसर पर हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार, ममता कालिया, मधु कांकरिया एवं नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से आई डॉ. संजीता वर्मा चिंतन-मनन सत्र में सम्मिलित हुईं। इसका विषय 'स्त्री लेखन की लोकप्रियता' था। इस दौरान ममता कालिया ने कहा कि संजीता वर्मा ने कहा कि नेपाल में भी लोग स्त्री के संघर्ष को अपने लेखन का विषय बना रहे हैं और विशेष



कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि। • फोटोन न्यूज

पाठको का प्यार मिल रहा है। स्त्री एक सशक्त औरत है। नहीं डॉ. संजीता वर्मा ने कहा कि नेपाल में भी लोग स्त्री के संघर्ष को अपने लेखन का विषय बना रहे हैं और विशेष

उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बेहद जरूरी है, इससे छात्रों का संवाद साहित्यकारों से होता है जो उनके लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि वे ममता कालिया को सुन रहे हैं। छात्रों को निरंतर ममता जी के संपर्क में रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के हिन्दी भाषा के प्रति प्रयास को सराहा। इस दौरान ममता डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पुष्पकान्त शर्मा, डॉ. अनिता निधि, डॉ. नन्दन पाण्डेय, डॉ. प्रतिभा प्रसाद आदि उपस्थित थे।

इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा दूसरे दिन कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। जिसमें दंगल, विज्ञान रचना, लघुनाटिका (प्रथम चरण), वृत्तचित्र एवं रोल्ले संचार, नृत्य नाटिका, भाषा रूपांतरण, साहित्य के रंग (रंगीली) प्रश्नोत्तरी (द्वितीय चरण) इत्यादि। इन प्रतियोगिताओं में देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चक्रधरपुर, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, गर्वमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिका का प्रदर्शन किया।

खबरें राउरकेला की

ओड़िशा के छोटे शहरों के इमारतों में सांसद धीरज साहू ने छुपाए थे 351 करोड़ नकदी

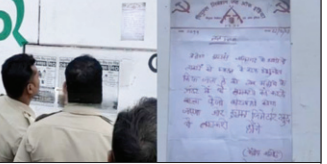
ROURKELA :



शराब कारोबारी और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के विभिन्न पतनों से 351 करोड़ रुपये की नकदी जब्त होने के मामले में आवक विभाग ने पहली बार बयान जारी किया है। विभाग ने कहा कि छापेमारी के दौरान 351 करोड़ रुपये के अलावा 2.80 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण भी जब्त किये गये। 329 करोड़ रुपये की नकदी का एक बड़ा हिस्सा बलांगीर जिले के सुदापाड़ा और टिटिलागढ़ और संबलपुर जिले के खतराजपुर सहित ओड़िशा के छोटे शहरों में पुरानी इमारतों के छिपे हुए कमरों में छिपाया गया था। ओड़िशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में 30 से अधिक परिसरों में आईटी संचालन हुआ। समूह का व्यवसाय रांची के एक परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आवक विभाग ने ओड़िशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 10 जिलों के 30 से ज्यादा इलाकों में कार्यवाही है। तलाशी अभियान के दौरान कागज और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य पाए गए और जन्म किए गए। जब्त किए गए सबूतों के प्रारंभिक विश्लेषण से मूल देशी दारू की बेहिसाब बिक्री के रिकॉर्ड, अघोषित नकदी का विवरण सामने आया।

गो चालान के विरोध में सुंदरगढ़ शहर में पीएलएफआई का पोस्टर, जांच में जुटी पुलिस

SUNDARGARH :



सुंदरगढ़: प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन ने गो चालान के विरोध में सुंदरगढ़ में पोस्टर चस्पा दिए हैं। सुंदरगढ़ टाउन पुलिस स्टेशन के पास निजी बस स्टैंड के निकट यह पोस्टर ओवर ब्रिज की दीवार पर चिपका हुआ है। पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन ने इस पोस्टर में गो को चलाना को बंद करने के लिए कहा गया है। इसमें लिखा गया है कि अगर इसे नहीं बंद किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। पोस्टर पर केंद्रीय क्रमेटी के प्रेम कुमार यादव के तलाक़ है। इससे स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पूर्व से ही सुंदरगढ़ झारखंड सीमा क्षेत्र में पीएलएफआई संगठन काफी सक्रिय था। 2014 में पुलिस द्वारा 6 पीएलएफआई के सदस्यों एनकाउंटर के बाद उनके गतिविधि कम हो गया था। परंतु आज का पोस्टर एक बार फिर से पीएलएफआई ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।

अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण

ROURKELA :



राउरकेला के अतिरिक्त जिलापाल और नगर निगम आयुक्त डॉ. शुभकर महापात्र ने कल शाम राउरकेला के विभिन्न स्वास्थ्य और उपचार केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ एम्बुलेंस सेवाओं की भी जांचकारी ली। डायरिया की स्थिति में लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए उपचार केंद्र (आरोग्य) राज्य सरकार के निर्देशानुसार राउरकेला शहर के सभी 10 स्वास्थ्य एवं उपचार केंद्र (आरोग्य) 24 घंटे खुले रहते हैं।

कबड्डी प्रतियोगिता में हृषिकेश राय कॉलेज बना विजेता

ROURKELA :



युवा खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए आयोजित 'नुवा-ओ युवा ओडिशा नवीन ओडिशा' खेल उत्सव कार्यक्रम में शुक्रवार को पुरुष एवं महिला वर्ग में कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच आयोजित किया गया। पुरुष वर्ग में हुए फाइनल मुकाबले में हृषिकेश राय कॉलेज विजेता बना, वहीं राउरकेला स्टील प्लांट हार गया। महिला वर्ग में हुए फाइनल मुकाबले में राउरकेला स्टील प्लांट ने म्यूनिसिपल कॉलेज से हारकर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया।

राउरकेला में डायरिया से एक और मौत

ROURKELA :



राउरकेला में डायरिया से एक और व्यक्ति की मौत हो गयी। मृतक 42 वर्षीय पंकज मंडल हैं। वह अपने परिवार के साथ पावर हाउस रोड पर रहता था। उनकी 7 साल और 4 साल की बेटी और बेटा यहां हैं। पंकज की कल रात जेपी अस्पताल में मौत हो गई। डायरिया के कारण पंकज को पहले हाईटेक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें जेपी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। डायरिया होने के बाद पंकज को दो किडनी पर असर पड़ा जेपी अस्पताल में उनका दो बार डायलिसिस भी हुआ।

भाजपा युवा मोर्चा ने महामारी रोकथाम में विफल होने का आरोप लगा किया घेराव



राउरकेला : भाजपा पानपोष जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष सुर्यकांत मोहंती के नेतृत्व में गुरुवार को युवा मोर्चा कार्यक्रमों में हैजा को रोकने में सरकार की विफलता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कहा कि यह बहुत दुःखद है कि राउरकेला महानगर निगम के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में हैजा फैलने से कई कीमती जानें चली गईं। उन्होंने महानगर निगम की अक्षमता और आम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की विफलता के लिए राज्य सरकार को कड़ी आलोचना की। आरजीएफ और अन्य अस्पतालों में जल्दी दवाएं उपलब्ध कराने, अस्पतालों में जल्दी बिस्तरों की व्यवस्था करने, संक्रमित इलाकों में प्रशासन हर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। मुफ्त भोजन, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करना, स्कूल संस्थानों में जागरूकता उपाय करना, प्रशासन की ओर से संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाना। इस कार्यक्रम में जिला विधानसभा नेता ललितिका पटनायक, प्रदेश प्रवक्ता धीरेन सेनापति, राज्य महिला मोर्चा उपाध्यक्षिनेता कल्पना लोका, सुब्रत पटनायक, शशांक जेना, अबोद रॉय कैलाश राउत, कमलेश साहा, हिरोज रॉय, शिबा नंद बेहरा श्रीकांत राय, आशीष शर्मा, गौरी नायक, आतिश कुमार, प्रशांत बारिक, राधे नाग, किशोर बंडोल, राजकिशोर भंज के सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए।

26 जनवरी से शुरू होगा प्रो कबड्डी लीग



पटना । प्रो. कबड्डी लीग सीजन-10 शुरू होते ही लोगों पर कबड्डी का खुमार चढ़ गया है। इसमें पटना पाइरेट्स की टीम अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। चार साल बाद पटना में फिर से कबड्डी का रोमांच देखने को मिलेगा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रो कबड्डी लीग का आयोजन 26 जनवरी से शुरू होगा, जो 31 जनवरी तक होगा। पटना में इन छ दिनों में कुल 11 मैच होंगे। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स

कॉम्प्लेक्स में होने वाला यह मुकाबला इस बार कुछ खास होगा, क्योंकि इसके लिए इनडोर स्टेडियम के मल्टी पर्पस हॉल पलोर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया है। यहां के मल्टी पर्पस हॉल पलोर को वियतनाम के मेपल वुड से बनाकर तैयार किया गया है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहर का एक मात्र इंडोर स्टेडियम है। इसके मल्टी पर्पस हॉल पलोर को एक नया लुक दिया जा रहा है।



बिहार खेल प्रोडिक्शन के महानिदेशक रवीन्द्र शंकर ने बताया कि इस हॉल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरे देश में यह पहला मल्टी पर्पस हॉल है, जिसके वुडन फ्लोर 7 लेयर से बने हैं। इसमें मेपल वुड और पाइन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे वियतनाम से मंगाया गया है। इससे पहले अमेरिका से मंगाए लकड़ी से पलोर को तैयार किया गया था इसके 7 लेयर में सबसे

निचला लेयर रबर का है, जो 15 मिमी का है। फिर 18 मिमी का पाइन वुड का सब-फ्लोर है। उसके बाद 39 मिमी का कोल का लेयर है। चौथा और पांचवा लेयर 18 मिमी का पाइन वुड का सब-फ्लोर है। इसके बाद पतला सा शॉक अब्सॉर्बेशन फिल्म का लेयर है। आखिरी में सबसे ऊपर 22 मिमी का मेपल वुड का लेयर है। इन 7 लेयरों को तैयार करने में 1 करोड़ 4 लाख रुपए का खर्च आया है।



इस पलोर को बनाने के लिए हैदराबाद से कारीगर आए थे। यह 12 हजार स्क्वायर फीट में फैला है। इस हॉल में एक साथ 25 सौ लोग बैठ सकते हैं। इन 7 लेयर से खिलाड़ियों को खेलने में कुशल इफेक्ट और बाउंस मिलेगा। इसमें चोट लगने के चांस काफी कम है। रबर पैड और थिन फिल्म शॉक अब्सॉर्बेशन का काम करता है। मेपल वुड वॉटर रजिस्टर्ड है रवीन्द्र शंकर ने बताया कि

इस पूरे सफेस में कांटी नहीं दिखेगी। दरअसल, इसमें ऊपर से फिक्स करने के लिए छ-शेड कोल लगाई गई है। जिसे फिक्स करने से कांटी बाहर से नहीं दिखेगी, वह अंदर ही रहेगी। इस मल्टी पर्पस हॉल में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सेपकटकरा, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, वेडमिंटन, आदि जैसे खेल भी खेले जा सकते हैं इस बार पटना पाइरेट्स का टाइटल स्पॉन्सर खुद बिहार सरकार है।

संक्षिप्त डायरी

पाठक ने डायट का किया निरीक्षण



गोपालगंज । शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक गोपालगंज पहुंचे, इस दौरान उन्होंने डायट का किया निरीक्षण करते हुए अपने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के लिए आए शिक्षकों के खाना समेत कई मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। दरअसल पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत केके पाठक थावे स्थित डायट में देर रात पहुंचे। उनके आगमन के पूर्व डायट में थावे में चहलकदमीया देखने को मिली। जैसे ही वे डायट पहुंचे वैसे ही वहां मौजूद अधिकारियों और शिक्षकों ने उनका स्वागत किया इस दौरान अपर मुख्य सचिव केके पाठक शिक्षकों से संवाद की साथ ही डायट कैम्पस का निरीक्षण करते हुए डायट का रंगरोशन कराने और स्वच्छ पानी को लेकर आरओ लगाने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण के लिए आए शिक्षकों के खाना का भी जांच किया। साथ ही उन्होंने रसोइया से खाने का मेन्यू पूछा व खाने के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से भी खाने की गुणवत्ता को लेकर बात की। डीएलएड के फाइनल ईयर के छात्रों ने उनसे फाइनल परीक्षा मई माह में कराने की अपील की। जिससे वे लोग अगस्त में होने वाली नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। केके पाठक ने आश्वासन दिया कि अगस्त में होने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। उससे पहले डीएलएड की परीक्षा ले ली जायेगी।

परीक्षा देने जा रहे छात्र को ट्रक ने कुचला

जमुई । जमुई में बीए पाठ वन की परीक्षा देने के लिए जा रहे एक बाइक सवार छात्र को तेज रफतार ट्रक ने कुचल दिया। जिससे एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। मृतक की पहचान जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत चनवेरिया गांव निवासी सुनील यादव के पुत्र नीतीश कुमार (20) के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश शुक्रवार की सुबह अपने एक दोस्त चंदन कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर बीए पाठ वन की परीक्षा देने के लिए सिद्धारा प्रखंड स्थित धनराज सिंह कॉलेज जा रहा था। जैसे ही वह बायपास रोड स्थित शमुन वाटिका के पास पहुंचा तभी सामने से आ रहे एक तेज रफतार ट्रक ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले बाइक और मैजिक की टक्कर हुई थी। जिसके बाद पीछे से आ रही तेज रफतार ट्रक ने युवक को कुचल दिया। जिससे यह घटना हुई है। घटना की जानकारी के बाद टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। टाउन थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। जबकि घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित दिखे और पुलिस प्रशासन को आरोपित ट्रक चालक के खिलाफ शक्ति से कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया गया

राजद नेता शिवानंद तिवारी ने भाजपा पर साधा निशाना

कैमूर । कैमूर में एक निजी कार्यक्रम में आए राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा लोकतंत्र संकट में है दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा विपक्ष को बाहर निकाल दिया जाए। संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष संसद में चर्चा नहीं बल्कि उनके नेता बाहर चर्चा करते हैं। साथ ही जिन लोगों ने सुरक्षा में सेंध लगाए वह काफी पढ़े लिखे डिग्री धारक थे जो बेरोजगार थे, और जो इनका मुखिया ललित झा था उनके घर दरंगाम में पोस्टर लगा है कि वह क्रांतिकारी योद्धा था। वह भगत सिंह को मानने वाले थे पूरी जमात भगत सिंह के नाम पर एकत्रित हुई थी।

सीएम ने महिला एंकर का किया अभिनंदन



पटना । सीएम नीतीश ने महिला एंकर का अभिनंदन किया। गुरुवार को नीतीश कुमार पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे थे। इस दौरान महिला एंकर ने मंच पर सीएम नीतीश कुमार का स्वागत किया। उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका भी अभिनंदन है। इसके बाद महिला एंकर ने जवाब दिया- थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां तीन दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो-2023 का उद्घाटन करने पहुंचे थे।

26 दिसंबर को लगेगा जाँब कैम्प, मिलेगा रोजगार



वेगूसराय । वेगूसराय में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। रोजगार कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम दिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर श्रम संसाधन विभाग द्वारा वेगूसराय जिला नियोजनालय में 26 दिसंबर को जाँब कैम्प का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक लगने वाले इस जाँब कैम्प में 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेरोजगार भाग ले सकते हैं, जहाँ कि इच्छुक अभ्यर्थी नियोजक से दिए जाने वाले काम के संबंध में जानकारी लेकर

आवेदन और बायोडाटा जमा करेंगे। इस जाँब कैम्प में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों का एनएसपी पोर्टल पर निर्बाधित होना हर हाल में अनिवार्य है। जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी वेलस्पॉन इंडिया लिमिटेड श द्वारा ट्रेनिंग ऑपरटर के पोस्ट पर आठवीं पास से लेकर आईटीआई तक के एक सौ बेरोजगारों को चयन कर गुरजरात में काम करने का मौका मिलेगा। यह जाँब कैम्प 18 से 35 वर्ष तक के बेरोजगार के लिए है। चयनित को 12500 से लेकर 15500 वेतन के साथ रहने और खाने की भी सुविधा मिलेगा।

घर के अंदर तहखाना बनाकर रखी थी शराब जब्त

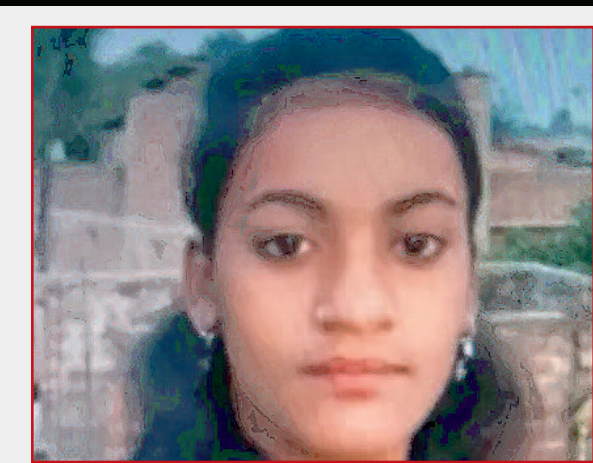
शेखपुरा । शेखपुरा में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की एक टीम ने जिले के मालदह गांव में छापेमारी कर एक तस्कर के घर के अंदर से शराब का जखीरा को बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मशकत के बाद शराब को जब्त कर लिया।



अभियान का नेतृत्व उत्पाद अधीक्षक सुदेश्वर लाल ने की। जबकि छापामार दल में उत्पाद दरोगा निशा कुमारी तथा एएसआई अनिल सिंह के अलावा बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल शामिल थी।

चार दिनों से लापता किशोरी का पोखर में मिला शव

समस्तीपुर । समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र के पुसहो गांव से चार दिनों से लापता किशोरी का शव पोखर में मिलने से गुरुवार को इलाके में सनसनी फैल गई। मृत किशोरी गांव के सहदेव महतो की पुत्री पूजा कुमारी 14 वर्ष बताई गई है। वह नवम वर्ग की छात्रा थी। घटना की सूचना पर बिथान थाने की पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गुरुवार देर शाम सदर अस्पताल भेजा मृत किशोरी के पिता सहदेव महतो ने बताया कि वह अपनी पत्नी का उपचार करने के लिए बेगूसराय गए हुए थे। वह कुछ पशु भी पाल रखे हैं जिस कारण उनकी पुत्री रोजाना की तरह 17 दिसंबर को घास काटने के लिए चौर की ओर गई थी। लेकिन वह नहीं लौटी। जब इन्हें जानकारी



मिली तो बेगूसराय से लौटने के बाद उसकी खोजबीन शुरू की। लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। जिसके बाद उन्होंने दो दिन पूर्व बिथान थाने को सूचना दी। बिथान पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और खोजबीन शुरू की। लेकिन उनकी पुत्री का कुछ पता नहीं चल सका। गुरुवार दोपहर गांव के ही कुछ लोगों ने देखा कि पुसहो चौर स्थित पोखर में उनकी पुत्री का शव उपला रहा है। घटना की सूचना के बाद

गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकाला इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। मृतक के पिता का कहना है कि उन्हें गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं संभव है। घर में घास काटने के लिए उनकी पुत्री गई हुई थी। इसी दौरान पोखर में पैर फिसलने के कारण उसकी डूबकर मौत हो गई होगी। बिथान थाना अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि किशोरी घास काटने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान पोखर में डूबने से मौत हुई है। उसके पिता ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है ना ही कहीं पर गला दबाने या शरीर पर जख्म का निशान है। शव जबत कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना को लेकर एक यूडी केस दर्ज की गई है।

बक्सर के 4 युवक की हजारीबाग में मौत

बक्सर । हजारीबाग में गुरुवार को घुए से दम घुटने के कारण बक्सर के चार मजदूरों की मौत हो गई है। घटना कटकमदाग थाना क्षेत्र के रसूलगंज की है। चारों के परिवार वालों को केवल उनके घायल होने की सूचना मिली है। फिलहाल सबसे परिजन हजारीबाग के लिए रवाना हो गए हैं। चारों युवकों के परिजन सूचना मिलते ही घबरा गए। मृतकों की पहचान 20 साल के राकेश कुमार, 21 साल के अखिलेश कुमार, 20 साल के प्रिंस कुमार और 19 साल के अरमान अलि के रूप में हुई है। चारों युवक सिकरील थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें राकेश, प्रिंस और अरमान बसाव कला गांव का रहने वाला था। वहीं, अखिलेश बाराडीह का रहने वाला था। परिजनों का कहना है कि उनको शाम चार बजे चौकीदार के माध्यम से पता चला कि वहां कुछ हुआ है जिसमें गांव



के कुछ लोग घायल हो गए हैं। अरमान के दादा मो. मुख्तार ने बताया कि पता चला कि हजारीबाग में हमारे गांव के लड़कों के साथ हादसा हो गया है। जबकि सबसे छोटे भाई इरफान अलि ने कहा कि दो दिन पहले भैया से बात हुई थी। मैं पढ़कर भैया तो पता चला कि भैया के साथ हादसा हो गया है। पापा बाहर रहते हैं। मां सूचना मिलने के बाद हजारीबाग गई है।

बता दें कि अरमान की शादी नहीं हुई थी। वह तीन भाई और एक बहन था। छोटी बहन ने कहा कि थाना से कॉल आया था। कहा गया कि आग लगने से हादसा हो गया है। कुछ लोग घायल हो गए हैं। मां बोली कि हजारीबाग जा रहे हैं, लेकिन वह वापस आ गईं। पापा ने किसी रिश्तेदार को पता करने वहां भेजा है राकेश सिंह के पिता कमलेश सिंह ने बताया कि हमें

खबर मिली है कि वह घायल है। उसको हजारीबाग भेजा गया था। राकेश तीन भाइयों में माझिल था। हम लोग खेती करते हैं। वह घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दवाई कंपनी में काम करता था। उससे परसो दिन में बात हुई थी, आज कॉल किया तो फोन पर रिंग जा रही है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। हड़य, प्रिंस के दादा दुग्गुन महतो ने बताया कि सूचना मिली कि वह जल गया है। कोयला जलाया था, चार लोग सो रहे थे। चारों हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां से बताया कि प्रिंस बीमार है। आकर मिल लें। बच नहीं पाएगा। प्रिंस के पिता हजारीबाग के लिए निकले हैं। प्रिंस के दादा जी बोलते बोलते फफक पड़े। परिजनों को मौत की कोई सूचना फिलहाल नहीं दी गई है। अखिलेश की मां पुष्पांजलि देवी ने कहा कि मुझे पता चला है कि तबीयत खराब है।

मोबाइल के लिए 3 युवकों को मारे चाकू एक की मौत

छपरा में मोबाइल लूट रहे बदमाशों ने तीन युवकों को चाकू मार दिया। एक युवक की मौत हो गई। दो युवकों की हालत गंभीर है। इन्हें इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश युवकों को चाकू मारते रहे और युवक मदद मांगते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया, जबकि मौके पर 50 से अधिक लोग मौजूद थे। घटना नगर थाना क्षेत्र के योगिनियां कोठी फुट ओवरब्रिज के पास की है। जब तीनों युवक जमीन पर पिर गए और बदमाश भाग गए, तब लोग उन्हें अस्पताल ले गए। मृतक की पहचान मुफसिल थाना



क्षेत्र के गड़खा ढाला स्थित आजाद नगर निवासी अंकित कुमार (20) के रूप में हुई है। दो अन्य घायलों की पहचान सचिन कुमार (17) पिता सुरेंद्र साह और आशीष कुमार (19) पिता अभय साह के रूप में हुई है। अस्पताल में भर्ती सचिन

कुमार ने बताया कि शाम को हम लोग चाय पीकर वापस घर जा रहे थे। ओवरब्रिज से उतरने के बाद 6 की संख्या में आए बदमाश मोबाइल छीनने लगे। जब हम तीनों दोस्तों ने विरोध किया तो उन लोगों ने चाकू किए जाने पर अपराधियों ने हमला किया है।

एंबुलेंस में नहीं मिला ऑक्सीजन मरीज की मौत

हाजीपुर । हाजीपुर में एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक मरीज की मौत हो गई। मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन के साथ पटना रेफर कर दिया था। एंबुलेंस में मरीज के परिजन ऑक्सीजन के लिए इंतजार करते रहे। परिजन 15 मिनट तक ऑक्सीजन-ऑक्सीजन चिल्लाते रहे, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने की वजह से एंबुलेंस कर्मी दूसरे एंबुलेंस के इंतजाम करने की दलील देते रहे। इसी बीच मरीज मो. ताहिर (65) की मौत हो गई। परिजन ने अब अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि डॉक्टर का कहना है कि रेफर करते समय ही बता दिया गया था कि जिस एंबुलेंस में ऑक्सीजन हो उसी से जाइएगा। डॉक्टर के मुताबिक, परिजन की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है, क्योंकि वो किसी परिजन के आने का इंतजार कर रहे थे। मृतक के भाई मो. साहिल ने बताया कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहां आए तो ऑक्सीजन लगाया गया। फिर कहा कि पटना लेकर जाओ, लेकिन एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था।

सांसदों के निलंबन के खिलाफ पटना में प्रदर्शन

पटना । संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार (22 दिसंबर) को क.ठ.क.अ के घटक दल पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सांसदों के संसंधान के विरोध में देशभर में प्रदर्शन करने को कहा है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन में शामिल होना है। पटना में विरोध मार्च इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू हुआ। इंडिया गठबंधन के आह्वान पर इससे जुड़ी पार्टियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का जो निलंबन हुआ है, उसे वापस लिया जाए। बिहार के बाकी जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शन हो रहा है। इसे लेकर आरजेडी ऑफिस में 21 दिसंबर को बैठक की गई थी। इसमें



आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशावाहा, सीपीआई (माले) के धीरेन्द्र झा, सीपीआई एम के अरुण कुमार, सीपीआई के रामबाबू कुमार शामिल हुए थे। कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता शकील अहमद खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। 113 दिसंबर को लोकसभा में दो शख्स घुस आए थे, उन्हें सांसदों ने पकड़कर पुलिस

मुद्दा उठा था। विपक्षी दलों ने सांसदों के संसंधान की निंदा की और इसके खिलाफ विरोध करने का फैसला किया। 21 दिसंबर को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसदों ने पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान खड़गे ने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चूक पर जवाब दे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम वाराणसी, अहमदाबाद जा रहे हैं, वे हर जगह बोल रहे हैं, संसद में सुरक्षा चूक पर नहीं बोल रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद के सिक्वोरिटी लेस पर कुछ नहीं कहा। हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार सदन नहीं चलने देना चाह रही है। विपक्ष की आवाज दबा रही है।

दूरसंचार में सुधार

देश में आजादी से पहले गिनती के टेलीफोन हुआ करते थे, पर अब भाति-भाति के फोन सम्बन्धकार की संख्या एक अरब की संख्या को पार कर चुकी है। जब 74 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपयोगी हो गए हैं, तब दूरसंचार संबंधी कानूनों को बदलना बहुत जरूरी है। संसद में दूरसंचार विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है और इसकी खूब चर्चा हो रही है। जिस देश में ज्यादातर लोगों के हाथों में फोन हो, वहां उससे संबंधित किसी कानून का बनना या बदलना स्वाभाविक ही रोचक विषय है। यह विधेयक उपग्रह स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन की अनुमति देता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस व्यवस्था को प्राधिकरण व्यवस्था से बदल देता है। कानून में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के उपायों को मजबूत करता है और विवाद समाधान के लिए चार-स्तरीय संरचना भी प्रदान करता है। नया विधेयक इसलिए भी मायने रखता है, क्योंकि यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933) का भी स्थान लेगा। भारत में दूरसंचार क्षेत्र में जिस ढंग से बदलाव हुए हैं, उसमें निजी क्षेत्र की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। निस्संदेह, नया दूरसंचार कानून सरकार के हाथ मजबूत करेगा। विगत दशकों में हमने देखा है कि देश में सिम कार्ड एक तरह से गली-गली में बटे हैं। मोटे तौर पर दो ही बड़ी कंपनियां मैदान में मजबूत हो गई हैं, पर जब लगभग छह कंपनियां सक्रिय थीं, तब किसी भी मोहल्ले में लोगों से ज्यादा सिम कार्ड पाए जाते थे। जाहिर है, सिम कार्ड लेने के लिए फजीवांदा भी खूब हुआ। बढ़ती सुविधा के साथ साइबर ठगी को भी बल मिला, पर नए कानून के लागू होने के बाद अगर कोई गलत ढंग से सिम लेता है, तो उसे तीन साल की सजा या 50 लाख रुपये तक के आर्थिक दंड का भागी बनना पड़ सकता है। ऐसे कड़े कानून के बाद अगर फर्जी ढंग से सिम कार्ड का बंटना रुक जाएगा, तो यह निस्संदेह देशहित में होगा। इससे साइबर ठगी रोकने में भी मदद मिलेगी। ग्राहक सत्यापन में कड़ाई बरती जाएगी, इसकी शिकायत हो रही है, लेकिन भारत जैसे देश में, जहां तकनीक का दुरुपयोग आम बात है, यह उचित है। संदिग्ध या अपराधी ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं पर निगरानी का भी साया रहेगा। गोपनीयता की चिंता जताई जा रही है, पर जरूरी होने पर गोपनीयता में संघ सरकार के लिए मजबूरी है। सरकार किसी संदेश को बीच में ही रोकने में सक्षम होगी। हां, प्रेर को छूट दी गई है। वास्तुएव इत्यादि के जरिये संचिन्ध थीं, तब किसी और ओटीडी मैसैजिंग की भी निगरानी संभव हो जाएगी। गौर करने की बात है कि दूरसंचार पर सरकार का कब्जा इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि दूरसंचार का ज्यादातर काम निजी कंपनियों के हाथों में है और निजी कंपनियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से विदेशी पैसा भी लगा हुआ है। विशेष रूप से उपद्रवग्रस्त इलाकों में सरकार पहले भी किसी नेटवर्क को अपने हाथ में लेती रही है, अब इस कानून के जरिये उसे इस काम में आसानी होगी। आम आदमी के नजरिये से देखें, तो दूरसंचार के क्षेत्र को अच्छी सेवाओं के पैमाने पर अभी बहुत आगे जाना है और तकनीक को ज्यादा सहज होना है। इन कानूनों में किए गए अनेक प्रावधान बहुत जरूरी हैं, अगर यह भावी कानून आम आदमी को सुरक्षित करता है, तमाम तरह की ठगी से बचाता है, तो यह कानून सच्चे अर्थों में प्रशंसनीय हो जाएगा। ध्यान रहे, इस साल देश में दस लाख से ज्यादा साइबर ठगी के मामले हो चुके हैं।

मास्क ही बचाव

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में गुरुवार को कोरोना के 594 नए मामले दर्ज किए गए। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 2,669 हो गई, जो इससे एक दिन पहले 2,331 थी। देश में पिछले दो हफ्ते में कोरोना के 22 मरीजों की मौत हुई है। बुधवार तक देशभर में खट.1 वैरिएंट के 21 मामले पाए गए हैं। कोरोना के नए सब-वैरिएंट जेएन.1 ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। यह दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में एक तक इसके 21 मामले सामने आए हैं। कोरोना के सभी मामलों को देखा जाए तो बुधवार को देश भर में 624 नए केस मिले, जो 21 मई 2023 के बाद से यानी पिछले सात महीनों में एक दिन में दर्ज हुईं सबसे ज्यादा संख्या है। पिछले दो सप्ताहों में भारत में कोरोना से 16 मौतें हुई हैं। वैसे तो कोरोना की पिछली लहरों के मुकाबले यह संख्या गंभीर नहीं कही जाएगी, लेकिन शुरू में धीरे और फिर तेजी से फैलाव की इसकी प्रवृत्ति को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती। इसीलिए सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने टैस्टिंग बढ़ाने, सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने और सभी केंसों की रिपोर्टिंग करने पर जोर दिया। महामारी शुरू होने के बाद से ही हम कोरोना के चले जाने और इसके फिर से आ धमकने की योग्यताएं सुनते रहे हैं। यह बात समझने की है कि कोरोना वायरस कभी गया नहीं था। न ही वह जाएगा। यह हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है और यहीं बना रहेगा। समय-समय पर इसके नए-नए वैरिएंट आते रहेंगे और हमें उनसे बचने और निपटने के तरीके अपनाने रहने होंगे। जहां तक इसके नए सब-वैरिएंट जेएन.1 का सवाल है तो डब्ल्यूएचओ ने भी इस पर नजर रखने की जरूरत बताई है। यह ऐसे समय उभरा है, जब पहले टीका ले चुके या इसकी चोट में आ चुके लोगों में बनी एंटी बॉडी कमजोर हो चुकी है। इसके अलावा यह टंड का मौसम है, जो वायरस के अनुकूल पड़ता है। भारत और अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जब नए वायरस की जीनोम एनालिसिस बढ़ेगी तो इसके व्यवहार से पता चलेगा कि इसकी संक्रामक और मारक शक्ति कितनी कम या ज्यादा है। लेकिन अब तक अन्य देशों के अनुभव से ऐसा नहीं लगता कि इसकी मारक शक्ति ज्यादा है।

Social Media Corner

सब के हक में...

अपनी माँगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना हेमंत सरकार की असंवेदनशीलता और झुंझलाहट को दर्शाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उत्तरने में बुरी तरह विफल साबित हुए हैं, इसलिए वे लाठी के बल पर जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं।
(पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)



जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में एक बार गलती से अपराध हो गया है। जब छूट कर बाहर निकलें, तो उसे दोहराएं मत। जेल प्रशासन इनके कोशल विकास के लिए छोटे छोटे काम सिखाने की व्यवस्था करें। हमारे युवा जब जेल से बाहर निकलें तो इन्हें कमाने के लिए फिर अपराध न करना पड़े और ये भी सम्मान की जिंदगी जी सकें। आज मलकानगिरि जिला जेल में बंद आरोपियों से मिला और उनकी समस्याएं जानी।
(पूर्व सीएम रघुवर दास का 'एक्स' पर पोस्ट)



आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धनबाद आया है। शिपिर के जरिए लाखों लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अपने गांव, पंचायत, वार्ड में लगने वाले शिपिरों के जरिए आप भी राज्य सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य लें।
(मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के टिवटर अकाउंट से)



उत्तर प्रदेश : कैसे बना भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

ANALYSIS



शिवेश प्रताप सिंह

देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र 15.7 प्रतिशत जीडीपी योगदान के साथ पहले पायदान पर है। तो वहीं उत्तर प्रदेश 9.2 प्रतिशत जीडीपी के साथ दूसरे स्थान पर है। बीते कुछ समय से तमिलनाडु से कांटे की टक्कर में उत्तर प्रदेश को अब बढ़त मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। आइये जानते हैं की योगी का उत्तरप्रदेश कैसे आज से सात साल पहले असंभव से लगने वाले इस लक्ष्य को हासिल कर आगे बढ़ते हुए भारत के जीडीपी योगदान में प्रथम स्थान हासिल करने हेतु निरंतर प्रगतिशील है। किसी भी प्रदेश के लिए ऐसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मात्र घरेलू बाजार की निर्भरता को खत्म कर अपने निर्यात से पूरी दुनिया में व्यापारिक पैठ बनाने की आवश्यकता होती है। घरेलू बाजारों की मांग एवं क्रय शक्ति सीमित होती है जो एक सीमित राजस्व ही पैदा करने में सक्षम होती है। एक्सपोर्ट के माध्यम से एक विशालकाय बाजार के साथ अच्छे लाभ एवं राजस्व प्राप्त का रस्ता भी खुलता है। योगी सरकार को निर्यात का महत्व पता है इसलिए सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर ऐसी नीतियाँ एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे निर्यात प्रोत्साहन को प्रदेश में बढ़ावा मिले।

योगी ने कभी बीमारू माने जाने वाले उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा किया है। विक्षेपण मंच एसओआईसी के अनुसार संसेक्स तथा क्रेडिट लियोनिस् सिक्वोरिटीज एशिया आधारित रिपोर्ट्स के हिसाब से देश की जीडीपी में हिस्सा के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। यह परिणाम योगी सरकार द्वारा किए गए अनेक अहर्निश, ईमानदार एवं अनथक प्रयासों का परिणाम है। देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र 15.7 प्रतिशत जीडीपी योगदान के साथ पहले पायदान पर है तो वहीं उत्तर प्रदेश 9.2 प्रतिशत जीडीपी के साथ दूसरे स्थान पर है। बीते कुछ समय से तमिलनाडु से कांटे की टक्कर में उत्तर प्रदेश को अब बढ़त मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। आइये जानते हैं की योगी का उत्तरप्रदेश कैसे आज से सात साल पहले असंभव से लगने वाले इस लक्ष्य को हासिल कर आगे बढ़ते हुए भारत के जीडीपी योगदान में प्रथम स्थान हासिल करने हेतु निरंतर प्रगतिशील है। किसी भी प्रदेश के लिए ऐसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मात्र घरेलू बाजार की निर्भरता को खत्म कर अपने निर्यात से पूरी दुनिया में व्यापारिक पैठ बनाने की आवश्यकता होती है। घरेलू बाजारों की मांग एवं क्रय शक्ति सीमित होती है जो एक सीमित राजस्व ही पैदा करने में सक्षम होती है। एक्सपोर्ट के माध्यम से एक विशालकाय बाजार के साथ अच्छे लाभ एवं राजस्व प्राप्त का रस्ता भी खुलता है। योगी सरकार को निर्यात का महत्व पता है इसलिए सरकार द्वारा जमीनी स्तर

पर ऐसी नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे निर्यात प्रोत्साहन को प्रदेश में बढ़ावा मिले योगी सरकार के गंभीर प्रयासों के कारण ही कोविड जैसी महामारी की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उत्तर प्रदेश का निर्यात पिछले छह वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के डेटा के अनुसार 2016-17 में प्रदेश का निर्यात 84,000 करोड़ रुपये का था जो 2022-23 में बढ़कर दोगुने से अधिक यानी 1,74,000 करोड़ रुपये का हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा दो लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह सूचनाएं सिद्ध करती हैं कि कभी बीमारू राज्य का टैग लेकर घूमने वाला उत्तर प्रदेश योगी सरकार की क्रांतिकारी नीतियों के कारण भारत का नया एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का 60 प्रतिशत निर्यात दुनिया के 10 देशों विगतनाथ, नीदरलैंड, फ्रांस, चीन, मिश्र, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम तथा जर्मनी को होता है। 2022-23 में सबसे अधिक निर्यात 32,800 करोड़ अमेरिका को, 14,300 करोड़ संयुक्त अरब अमीरात को तथा लगभग दस-दस हजार करोड़ जर्मनी एवं यूनाइटेड किंगडम को हुआ। उत्तर प्रदेश से वर्तमान में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, दूरसंचार उपकरण, कॉटन, कृत्रिम फाइबर आदि के साथ गेहूँ, चावल, कालीन एवं हस्तशिल्प भी महत्वपूर्ण निर्यात सामग्री है। परंतु चीनके वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं उत्तर प्रदेश के

संपूर्ण निर्यात का 18.9 प्रतिशत है। इसके बाद कपड़ा उद्योग 9.5 प्रतिशत का योगदान करता है। केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए देशभर के कुछ महत्वपूर्ण शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस घोषित किया है जिससे कि निर्यात को एक समकित विकास में सम्मिलित किया जा सके एक्सपोर्ट एक्सीलेंस वाले शहरों में ऐसे शहरों को चयनित किया जाता है जिसकी उत्पादन सीमा 750 करोड़ रुपये से अधिक की हो और निर्यात क्षमता भविष्योन्मुख हो। आज भारत भर में केंद्र सरकार के द्वारा चिह्नित किए गए 43 सेंटर आफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हैं। इनमें 12 सेंटर अकेले उत्तर प्रदेश में हैं जो इस प्रदेश के निर्यात सामर्थ्य को बताते हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तर तरफ से स्थलीय एवं पहाड़ी सीमाओं के बीच स्थित है सामान्यतः या निर्यात प्रोत्साहन हेतु समुद्री सीमा किसी भी प्रदेश को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है लेकिन उत्तर प्रदेश के पास कोई समुद्री सीमा न होते हुए भी 12 सेंटर आफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की मौजूदगी प्रदेश सरकार के विकास के संकल्प को स्वयं बताती है। जलमार्ग से सस्ते यातायात का लाभ तटीय प्रदेशों को मिलता है लेकिन इस चुनौती के समाधान के लिए भी प्रदेश की योगी सरकार ने गंभीरता से कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश के उद्योगों को जलमार्ग से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। समुद्री बंदरगाहों की अनुपस्थिति में निर्यात की सुगमता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के भीतर शुष्क बंदरगाहों का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने के लिए कार्यरत है इसी क्रम में योगी सरकार ने सिंगापुर के स्टार कंसोर्सियम तथा संयुक्त अरब

अमीरात के सर्राफ ग्रुपके साथ-साथ हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड व अमेरिका की दो कंपनियों मॉबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बेस्ट बेट्टिंग ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है। वर्तमान में मुम्बदाबाद रेल लिंकड जॉइंट डोमेस्टिक एक्सिमट मिनल, रेल लिंकड प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल तथा कानपुर व दादरी में शुष्क बंदरगाह सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। जलमार्ग के लिए वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जलराज मार्ग संख्या एकप्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण एवं संवर्धन के द्वारा निर्यात को बढ़ाने पर है। इन पारंपरिक उद्योगों में भी दो ऐसे क्षेत्र टेक्सटाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल उत्पादन करने वाला प्रदेश है तथा राष्ट्रीय उत्पादन में 13.24 प्रतिशत का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश में लगभग ढाई लाख हैंडलूम बुनकर तथा चार लाख 21 हजार पावरलूम बुनकर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में निर्यातको और बढ़ाना चाहती है साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि इस उद्योग से जुड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति भी निर्यात से लाभान्वित हो सके क्योंकि कपड़ा उद्योग कम पूंजीनिवेश तथा अधिक मानवीय श्रम आधारित उद्योग है। 10 हजार की एक सिलाई मशीन दो लोगों को रोजगार दे सकती है। यही कारण है कि कपड़ा उद्योग न केवल निर्यात प्रोत्साहन कर सकता है अपितु बेरोजगारी को विकाराल समस्या का भी समाधान कर सकता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। यह योगदान उत्तर

प्रदेश के चार जिलों से हो रहा है। नोएडा के रेडीमेड कपड़े, मेरठ का स्पोर्टवेयर, कानपुर के बच्चों के कपड़े तथा लखनऊ के पारंपरिक चिठान इसमें अपना अहम योगदान दे रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार इन्हीं जनपदों में टेक्सटाइल उद्योग के निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान दे रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 58 स्पिनिंग मिल्स तथा 74 टेक्सटाइल मिलें चल रही हैं। कपड़ा उद्योग के निर्यात प्रोत्साहन से उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया होगा। वैश्विक स्तर पर चीन का शेनझेन शहर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का सबसे बड़ा ठिकाना है पूरे विश्व का 90% इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इसी शहर की देन है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रति बनते रहझानों के कारण अब प्रदेश केसाथ-साथ केंद्र सरकार भी उत्तर प्रदेश को चीन के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के एकाधिकार के प्रत्युत्तर में उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में वरीयता दे रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश ने 29,699 करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यात किया। केंद्र सरकार के मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 तक 300 बिलियन डॉलर मूल्य के विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। इसका एक तिहाई लक्ष्य यानी 100 बिलियन डॉलर उत्तर प्रदेश द्वारा पूरा किए जाने की अपेक्षा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण की 196 कंपनियां उत्तर प्रदेश में ही स्थापित हैं।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

चौधरी चरण सिंह जयंती विशेष : किसानों की बुलंद आवाज

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। उनका कब्जा था कि भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। जिस देश के लोग भ्रष्ट होंगे वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए देश के लोगों का आज भी मानना है कि चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति नहीं विचारधारा थे। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा यह साबित करने की कोशिश की कि किसानों को खुशहाल किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। उनकी नीति किसानों व गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की थी। उन्होंने किसानों की खुशहाली के लिए खेती पर बल दिया था। किसानों में उनकी उपज का उचित दाम मिल सके, इसके लिए भी वो बहुत गंभीर रहते थे। उनका कब्जा था कि भारत का संपूर्ण विकास तभी होगा जब किसान, मजदूर, गरीब सभी खुशहाल होंगे। चौधरी चरण सिंह की गिनती हमेशा एक ईमानदार राजनेता के तौर पर की जाती है। उन्होंने जीवन पर्यन्त किसानों की सेवा को ही अपना धर्म

माना और अपने अंतिम समय तक देश के गांव में रहने वाले किसानों, गरीबों, दलितों, पीड़ितों की सेवा में ही पूरी जिंदागी गुजारी। चौधरी चरण सिंह जाति प्रथा के कट्टर खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह एक कुशल लेखक भी थे। उनका अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार था। उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन भी किया। 29 मई 1987 को 84 वर्ष की उम्र में जब उनका देहांत हुआ तो देश के किसानों ने सरकार में पैरवी करने वाला अपना नेता खो दिया था। लोगों का मानना था कि चरण सिंह से राजनीतिक गतिविधि हो सकती हैं लेकिन चारित्रिक रूप से उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। इतिहास में उनका नाम प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान नेता के रूप में जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह ने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद करते हुए आभान किया था कि भ्रष्टाचार का अंत ही देश को आगे ले जा सकता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसम्बर, 1902 को गाजियाबाद जिले के नूरपुर गांव के चौधरी मीर सिंह के घर हुआ था। बाद में उनका परिवार नूरपुर से जानी खुर्द

गांव आकर बस गया था। 1928 में चौधरी चरण सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा लेकर गाजियाबाद में वकालत प्रारंभ की। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने के समर्थन में चरण सिंह ने हिंडन नदी पर नमक बनाया जिस पर उन्हें 6 माह जेल की सजा हुई। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चरण सिंह गिरफ्तार किए गए। 1942 में अगस्त क्रांति के माहौल में चरण सिंह को गिरफ्तार कर डेढ़ वर्ष की सजा हुई। जेल में ही चौधरी चरण सिंह की लिखित पुस्तक शिष्टाचार भारतीय समाज में शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है। चौधरी चरण सिंह खुद एक छोटे से गांव में एक किसान के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने गांव के किसानों, गरीबों के दुख-दर्द को नजदीक से देखा-जाना था। इसलिए उन्हें उनकी समस्याओं का बखूबी अहसास था। उनको जब कभी कहीं मौका मिलता वे गांव के किसानों की सेवा करने से नहीं चूकते थे। उनके दिल में हमेशा गांव के किसान ही बसे रहते थे। चौधरी चरण सिंह जीवन

पर्यन्त गांधी टोपी धारण कर महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी बने रहे। आज देश के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। उनको उनकी उपज का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते देश में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकारें भी किसानों के भले की सोचें और बना पाने में नाकाम रही है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां किसानों को झंसा देकर उनके वोट बटोर लेती है। फिर किसी का ध्यान किसानों की समस्याओं के समाधान करने की तरफ नहीं जाता है। ऐसे में आज देश के किसानों को चौधरी चरणसिंह जैसे सच्चे किसान हितैषी नेता की जरूरत है। जो उनके हक में खड़ा होकर किसानों की आवाज बुलंद कर सके व उनका वाजिब हक दिला सके। चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति में बड़े नेता थे। मगर इंदिरा गांधी के सहयोग से कुछ समय के लिए देश के प्रधानमंत्री बन कर उन्होंने देश में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ बने एक मजबूत गठबंधन को तोड़ा। उससे उनकी

प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात पहुंचा था। चौधरी को 1951 में उत्तर प्रदेश सरकार में न्याय एवं सूचना विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1952 में डॉक्टर प्रभाकर के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्हें राजस्व तथा कृषि विभाग का दायित्व मिला। एक जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में उनके बहुलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को खेती करने के अधिकार मिले। 1954 में उन्होंने किसानों के हित में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। चरण सिंह स्वभाव से भी कृषक थे तथा कृषक हितों के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। 1960 में चंद्रशानु गुप्ता की सरकार में उन्हें गृह तथा कृषि मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश के किसान चरण सिंह को अपना रहनुमा मानते थे। उन्होंने कृषकों के कल्याण के लिए काफी कार्य किए। लोगों के लिए वो एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा समाजिक कार्यकर्ता थे। उनके भाषण को सुनने के लिये उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटा करती थी। किसानों में चौधरी साहब के नाम से मशहूर चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 में

पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तब 1967 में पूरे देश में साम्प्रदायिक दंगे होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कहीं पता भी नहीं हिला था। 17 फरवरी 1970 को वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। 1977 में चुनाव के बाद जब केंद्र में जत्ता पार्टी सत्ता में आई तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। केंद्र में मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वे उप प्रधानमंत्री बने। बाद में मोरारजी देसाई और चरण सिंह के मतभेद हो गए। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक चौधरी चरण सिंह समाजवादियों तथा कांग्रेस के सहयोग से भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2001 में हर वर्ष 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने की जो परंपरा शुरू की थी उससे जरूर उनको साल में एक दिन याद किया जाने लगा है।

इंडिया : संभावनाएं और सिलसिले

व्या इंडिया ब्लॉक भारतीय मतदाताओं के सामने अपनी संरचना और सिद्धांतों का कोई ठोस प्रारूप पेश कर पाएगा? इस लिहाज से उसकी पिछली तीन बैठकें निराशाजनक साबित हुई हैं। पता नहीं, इस युक्ति के नेता जानते हैं या नहीं कि इस बार वे अगर कोई ठोस एजेंडा पेश करने में कामयाब नहीं रहते हैं, तो उन्हें अगले चुनाव में पहले से ज्यादा बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। पिछली 3 दिसंबर को जब हिंदी-पट्टी के तीन विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए, तो तमाम चुनाव शास्त्री भौंककर रह गए। भाजपा ने क्षेत्रीय क्षेत्रों को दरकिनार कर यह चुनाव लड़ा था। पार्टी को जबरदस्त सफलता हासिल हुई। ये तीनों राज्य पिछले चुनाव में भगवा दल के हाथ से सरक गए थे। भारतीय राजनीति में बरसों बाद किसी सत्तानायक के प्रति मतदाताओं का ऐसा जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। इंदिरा गांधी के बाद लोग भूल गए थे कि क्षेत्रों को दरकिनार कर सूबाई चुनावों में महज प्रधानमंत्री के काम और नाम पर भी बहुमत अर्जित

किया जा सकता है। यहां मैं मिजोरम की चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि वहां भाजपा की दवेदारी परंपरागत तौर पर कमजोर थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान के फैसले एक और तथ्य की मुनादी करते हैं। पिछले 10 सालों में ऐसा कई बार हुआ था, जब मतदाताओं ने प्रदेश के लिए एक, तो देश के लिए दूसरी पार्टी का चयन किया। ये तीनों राज्य भी पांच बरस पहले इसी प्रवृत्ति को बल प्रदान करने वाले साबित हुए थे। विधानसभा चुनाव गंवाने के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 36 में से 34 सीटें भगवा दल के कब्जे में आ गई थीं। उत्तर और पश्चिम भारत के अन्य राज्यों का भी यही रवैया था। मोदी इसीलिए मई 2019 में पहले से अधिक बेहतर बहुमत के साथ चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करने के इस चमत्कार को न केवल दोहराना चाहती है, बल्कि और बेहतर तरीके से उस पर सान चढ़ाना चाहती है। नए मुख्यमंत्रियों से भाजपा को नुकसान के बजाय लाभ इसलिए मिल सकता है, क्योंकि उनके प्रति जनता के मन

में कोई अरुचि नहीं है। वे नई दिल्ली के आदेशों का जस का तस अनुपालन करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। राजनीति का पुराना दस्तरू भी किराये के फैसले कई बार सत्ता संभाल चुका होता है, तो उसके दिमाग पर हुकूमत का एक निश्चित तौर-तरीका कब्जा जमाने होता है। नए सोच-विचार और प्रयोग उसे जोखिम नजर आने लगते हैं। इसके उलट पहली बार कामकाज संभाल रहे मुख्यमंत्री बेहचक कठोर फैसले लेने में कामयाब रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के हिमंत बिस्वा सरमा और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल इसके उदाहरण हैं। इन तीनों ने अपने-अपने राज्य में नई रीति-नीति का सूत्रपात किया। नया रातपुर, भोपाल और जयपुर में हमें यह प्रवृत्ति पांव पसारती नजर आएगी? इन तीनों स्थानों पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर प्रधानमंत्री ने जनता को जता दिया कि वह ह्यमोदी की गारंटीह मामले में इन मातहतों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। पता नहीं, कांग्रेस के लोग ऐसा सोचते हैं या नहीं, लेकिन

उन्हें रेवत रेड्डी जैसा प्रयोग तीनों हिंदीभाषी राज्यों में करना चाहिए था। इससे चुनाव प्रचार को ताजगी मिलती और जरूरत के अनुरूप निर्णय बदलने में भी संकोच नहीं किया जाता। अनिर्णय और यथार्थस्थितिवाद कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। राजस्थान में पिछली बार के सत्तारोहण के पहले से अशोक गहलोत और सचिन पायलट उलझे हुए थे। इस टकराव को दूर नहीं किया जा सका। गहलोत 72 वर्ष के हैं और चुनाव से पहले दावा करते हुए घूम रहे थे- ह्यमैं तो मुख्यमंत्री बन छोड़ना चाहता हूं, पर यह पद ही मुझे नहीं छोड़ता हूँ ऐसा लगता है कि इस कुरसी ने उनका साथ सदा-सर्वदा के लिए छोड़ दिया है। इसी तरह, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 77 वर्षीय कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा। कमलनाथ सत्ता-विरोधी लहर को भुनाने में बुरी तरह नाकामयाब रहे। चुनाव से कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भटकते हुए मैंने पाया था कि लोग शिवराज से नाराज नहीं हैं, पर उनमें परिवर्तन की जबरदस्त कामना है।

नए कानून में डॉक्टरों के लिए हल्की सजा का प्रावधान क्यों?

भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य कानून ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। तीनों विधेयकों को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। लेकिन नए कानून में डॉक्टरों की लापरवाह के लिए सजा को हल्की कर दी गई है। भारतीय संसद ने इस हफ्ते नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को पारित कर दिया, जो पुराने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान लेती। इस बिल में एक बदलाव है जो डॉक्टरों के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह जरूरी नहीं था। बीएनएस की धारा 106 में लापरवाही से हुई मौत के लिए अधिकतम 5 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। हालांकि, इलाज में लापरवाही के मामले में इस सजा को कम करके अधिकतम दो साल की जेल और जुर्माना कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह बदलाव भारतीय मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अनुरोध पर किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में डॉक्टरों के लिए कम सजा का प्रावधान। मेडिकल नैचुरलैजेंस कानून की तीन धाराओं के तहत आती है। इन धाराओं की व्याख्या कोर्ट के फैसलों से हुई है, जिनमें दो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। कोर्ट के फैसलों ने डॉक्टरों को लापरवाही के झूठे आरोपों से बचाने के लिए कई सुरक्षा कवच दिए हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में मेडिकल नेग्लिजेंस और पेशेवर लापरवाही के बीच अंतर बताया गया है। इसमें कहा गया था कि थोड़ी लापरवाही या गलत फैसला लापरवाही का सबूत नहीं है। इन सिद्धांतों को दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले में दोहराया गया था। मेडिकल प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता के कारण डॉक्टरों को मुकदमे दर्ज होने से भी बचाया गया है। उदाहरण के लिए, बिना किसी योग्य डॉक्टर की राय के कोई निजी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का परित्यक्त 109 लाख करोड़ पहुंचा

- एनआईपी में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की नई एवं पुरानी परियोजनाएं शामिल हैं

नई दिल्ली ।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) की शुरुआत 6,835 परियोजनाओं से हुई थी और वर्ष 2020-25 के बीच इसकी बढ़ती रही होकर 108.88 लाख करोड़ रुपये के कुल परित्यक्त के साथ 9,288 परियोजनाओं तक पहुंच चुकी है।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा कि एनआईपी में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे दोनों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की नई एवं पुरानी

बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। एनआईपी के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े 22 मंत्रालयों की तरफ से लागू की जा रही परियोजनाएं शामिल हैं। एनआईपी देशभर में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने वाली पहल है। एनआईपी से परियोजनाओं की बेहतर तैयारी होगी और बुनियादी ढांचे में घरेलू और विदेशी दोनों निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा।

वित्त वर्ष 2024-25 तक

पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पाने के लिए भी इसे अहम माना जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) महिलाओं को वित्तीय लाभ देने के साथ उन्हें अपने पैसों का हिस्सा रखने और सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी भी आयु वर्ग की महिलाएं न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम दो लाख रुपये जमा के साथ दो साल के लिए एमएसएससी खाता खोल सकती हैं। इस पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है जिसकी गणना तिमाही

आधार पर की जाती है। सरकार ने डक विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और निजी क्षेत्र के चार बैंकों को एमएसएससी संचालित करने के लिए अधिकृत किया है। हालांकि, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे कुछ ऋणदाताओं ने अभी तक यह योजना शुरू नहीं की है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना को मार्च, 2025 तक दो वर्ष के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसका खाता खोलने के लिए 31 मार्च, 2025 तक आवेदन जमा किया जा सकता है।

जोमैटो कर सकता है शिपॉकेट का अधिग्रहण

नई दिल्ली ।

ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म जोमैटो ने घरेलू लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदाता शिपॉकेट को लगभग 16,600 करोड़ रुपये से अधिक में अधिग्रहण करने की पेशकश की है लेकिन सौदे पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पिछले साल अगस्त में जोमैटो समर्थित शिपॉकेट, जिसे इंफो एज, टेमासेक और लाइटएक का भी समर्थन प्राप्त था, ने 3.35 करोड़ डॉलर जुटाए, जिससे इसका मूल्यांकन लगभग

1.2 अरब डॉलर हो गया। जोमैटो ने उसी महीने, क्रिक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकडिग और उसके वेयरहाउसिंग और सहायक सेवा व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा किया। जोमैटो के बोर्ड ने ब्लिंकडिग के अधिग्रहण के लिए 4,447 करोड़ रुपये के लेनदेन को मंजूरी दे दी। सहायक कारोबार 61 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। इस बीच शिपॉकेट कथित तौर पर यूएस-आधारित निवेश फर्म ट्राइब कैपिटल के नेतृत्व में 75-100 मिलियन तक फंड जुटाने के लिए शीप वीसी फर्मों के साथ बातचीत

कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग को लेकर बातचीत जारी है और शर्तें बदल सकती हैं। ट्राइब कैपिटल और शिपॉकेट दोनों ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की। बेंगलुरु मुख्यालय वाले शिपॉकेट का लक्ष्य आगे 12 से 18 महीनों में आईपीओ के लिए तैयार होना है। इसका लक्ष्य आगे 12 महीनों में एसएमबी को लगभग 100 करोड़ रुपये वितरित करना है। 2017 में लॉन्च किया गया, शिपॉकेट खुदरा विक्रेताओं

को शापिफाई, मैगैटो, वूकॉमर्स, जोहो और अन्य पर अपनी शापिंग वेबसाइटों को एकीकृत करने में मदद करने के लिए एक प्रौद्योगिकी स्टैक प्रदान करता है। शिपॉकेट देश भर में स्थित 45 से अधिक गोदामों के साथ अत्याधुनिक पूर्ति समाधान भी प्रदान करता है।



बैंकों को बड़े दिवालिया मामलों की हर महीने समीक्षा का निर्देश

नई दिल्ली.

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों को हर महीने शीर्ष 20 दिवालिया मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दिवालिया मामलों की समीक्षा के लिए कहा है क्योंकि दिवालिया अदालतों में मामलों को स्वीकार करने में देरी होती है। जोशी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के कामकाज

की भी समीक्षा करेंगी क्योंकि फॉसे कर्ज की वसूली में देरी हो रही है। सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एनएआरसीएल के प्रबंधन के साथ बैठक बुलाई थी। एनएआरसीएल की स्थापना वाणिज्यिक बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियों को संभालने और उनका निपटान करने के लिए की गई थी ताकि उनके बही-खाते साफ हो जाएं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक धन उपलब्ध हो सके। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह संसद को सूचित किया कि नवंबर 2024 तक एनएआरसीएल ने सितंबर

2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित दो लाख करोड़ रुपये के मूल लक्ष्य के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 11,617 करोड़ रुपये के फॉसे हुए ऋण का अधिग्रहण किया है। मंत्रालय ने कहा, एनएआरसीएल द्वारा अधिग्रहित कुछ खाते आईबीसी के तहत हैं और एनसीएलएटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद ही वसूली संभव है। इस प्रकार, शेष खातों में एनएआरसीएल ने 30 नवंबर 2023 तक केवल 16.64 करोड़ रुपये की वसूली की है। आईबीसी मामलों में भी देरी होती है, जिन्हें न्यायाधिकरणों में दाखिल होने में

ही एक साल से अधिक का समय लग जाता है, जबकि समाधान प्रक्रिया 360 दिन की समयसीमा से कहीं अधिक लंबी हो जाती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2019 से 2023 के बीच पांच वर्षों में सात लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंसा कर्ज माफ कर दिया। इन अटकली संपत्तियों में से 6.5 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 2023 में 94,000 करोड़ रुपये या मात्र 15 प्रतिशत की वसूली की गई है, जिसमें से आधे से अधिक बरामद राशि आईबीसी मार्ग के माध्यम से आई है।

आरबीआई की तरफ से एआईएफ में प्रतिबंध के बाद पीरामल ने किया प्रावधान

- पीरामल एआईएफ में 3,164 करोड़ के निवेश को कैपिटल फंड में समायोजित करेगा

मुंबई ।

पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और आईआईएफएल फाइनेंस ने एक्सचेंजों को सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंडों (एआईएफ) में लेनदारों के निवेश पर नियम लागू जाने के बाद उन्होंने प्रावधान करना शुरू कर दिया है। पीरामल एंटरप्राइजेज ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों (एआईएफ) में 3,164 करोड़ रुपये के निवेश को कैपिटल फंड या प्रावधानों के जरिये अपने बहीखाते में समायोजित करने का निर्णय लिया है। पीरामल के पास एनबीएफसी लाइसेंस है और वह पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस की मूल कंपनी भी है। कंपनी ने हाल ही में एक्सचेंजों को भेजी सूचना में कहा था कि बाकी 3,164 करोड़ रुपये में से 1,737 करोड़ रुपये का डायनस्ट्रीम निवेश एआईएफ में किया है, जो पीरामल की देनदार कंपनियां हैं। आईआईएफएल फाइनेंस ने खुलासा किया है कि उसकी सहायक आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड ने प्राथमिकता वाले वितरण मॉडल के तहत 161 करोड़ रुपये का निवेश किया है और अगर इसे नहीं बेचा



जा सका तो उसकी पूंजी से 100 फीसदी इसे घटाने की दरकार होगी। आईआईएफएल फाइनेंस ने निवेशकों को सूचित किया कि एआईएफ में उसके 909.81 करोड़ रुपये के निवेश में कोई डायनस्ट्रीम निवेश शामिल नहीं है, जिसके ऊपर उसका कर्ज या निवेश हो। फर्म का डायनस्ट्रीम फर्मों पर 3.28 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज है जबकि आईआईएफएल फिनटेक फंड में कुल 21.37 करोड़ रुपये निवेश है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि एडलवाइस का कुल निवेश एआईएफ में 11.4 फीसदी होगा और कुल कर्ज की हिस्सेदारी के तौर पर एआईएफ में निवेश करीब 4.4 फीसदी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों का इन निवेश में बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। इस बारे में जानकारी के लिए इंडियाबुल्स, एडलवाइस फाइनेंशियल, सुंदरम अल्टरनेट्स और नाबाड को भेजी गई प्रश्नावली का जवाब नहीं मिला।

टाटा नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल

-कार का माइलेज भी है काफी शानदार

नई दिल्ली ।

टाटा कंपनी की टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट मॉडल एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल हो गया है। कार का माइलेज भी काफी शानदार है। कार के हैडलैम्प अब आपको नए देखने को मिलेंगे। इसी के साथ फ्रंट बंपर और बोनट भी बिल्कुल नए और स्पोर्टी डिजाइन में दिया गया है। इसी के साथ कार के टेल लैंप्स और रियर बंपर का डिजाइन भी नया है।



वहीं कार में आपको नए मेटालिक कलर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो कार को और भी प्रीमियम लुक दे दिया गया है। नेक्सॉन की अपहॉल्टे स्टी को बदल दिया गया है और लैडराइट सीट्स का है और शन भी आपको मिलता है। वहीं बोनट के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। सीट्स को और ज्यादा कंफर्टबल बनाने के लिए कुशांग बढ़ा दी गई है। कार के फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले सेफ्टी जो नेक्सॉन की पहचान भी है। कार में अब आपको स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर 6 एयरबैग की सुरक्षा मिलती है। इसी के 360 डिग्री कैमरा, रियर

पार्किंग सेंसर, एबीएस, ईबीडी, चाइल्ड लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स सहित ढेरों फीचर्स मिलेंगे। वहीं कार में अब 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंड्रवर डिस्प्ले, क्लाइमेट कंट्रोल एसी, रियर एसी वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग सहित कई प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे।

इसके माइलेज की बात की जाए तो ये 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है। वहीं डीजल इंजन की बात की जाए तो ये 1.5 लीटर है और ये 118 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। कार का माइलेज 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक आता है। कार के इंजन में कंपनी ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। कार में पेट्रोल और डीजल इंजन कंपनी ऑफर कर रही है। पेट्रोल इंजन के तौर पर कार में 1.2 लीटर का रेक्ट्रॉन इंजन ऑफर करती है। ये इंजन 113 बीएचपी की पावर जनरेट करता है।



जीरो-डे वलनरेबिलिटी के लिए गूगल ने जारी किया इमरजेंसी पैच

सैन फ्रांसिस्को ।

गूगल ने क्रोम जीरो-डे वलनरेबिलिटी को संबोधित करने के लिए एक इमरजेंसी पैच जारी किया है, जिसमें उन्होंने माना है कि ऐसा हो रहा है। यह साल की शुरुआत के बाद से जारी किया गया आठवां पैच है। गूगल ने एक ब्लॉगपोस्ट में सुरक्षा सलाह जारी करते हुए लिखा, गूगल को पता है कि सीवीआई-2023-7024 (एक प्रकार का बग) मौजूद है। टेक जायंट ने स्टेबल डेस्कटॉप चैनल में यूजर्स के लिए जीरो-डे की खामी को ठीक कर दिया, गूगल को इसकी सूचना दिए जाने के एक दिन बाद विंडोज यूजर्स (120.0.6099.129/130), मैक और लिनक्स यूजर्स (120.0.6099.129) के लिए पैच किए गए वर्जन ग्लोबल लेवर पर जारी किए गए। बग की खोज और रिपोर्ट गूगल के थ्रेट एनालिसिस ग्रुप (टीएजी) के क्लेमेट लेसिने और व्लाद स्टोलारोव ने की थी। ब्लीपिंग कंप्यूटर के अनुसार, टीएजी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य गूगल करंटमर्स को स्टेट-स्पाईड अटैक से बचाना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोजिला फायरफॉक्स, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट एज सहित कई वेब ब्राउजर रीयल-टाइम टाइम कम्प्यूनिक्शंस (आरटीसी) क्षमताओं (जैसे, वीडियो स्ट्रीमिंग, फाइल शेयरिंग और वीओआईपी टेलीफोनी) प्रदान करने के लिए जावा क्रिप्ट एपीआई का उपयोग करते हैं। गूगल ने कहा, बग डिपेंडेंस और लिंक तक एक्सेस तब तक प्रतिबंधित रखा जा सकता है, जब तक कि अधिकांश यूजर्स को समाधान के साथ अपडेट नहीं किया जाता है। इस बीच, गूगल यूजर्स को प्रोडक्ट अडिस्टेंस प्रदान करने के लिए अपने कुछ हेल्प पेज पर एक नया एआई सपोर्ट अडिस्टेंस चैटबॉट शुरू कर रहा है।

भारतीय स्टार्टअप्स में 35 हजार से ज्यादा नौकरियां गईं, 2024 में भी छंटनी रहेगी जारी

नई दिल्ली।

पिछले दो साल में भारतीय स्टार्टअप्स में 35,000 से ज्यादा लोगों ने नौकरी से हाथ धोया है, और 2024 में भी नौकरियों में कटौती बरेकटोक जारी रहने की संभावना है। 2022 में बायजू, ओला, अनपेकडमी, ब्लिंकडिग और वाइटहैट जूनियर, स्किल-लिक, गो मैकेनिक, शेर चैट और जेस्टमनी जैसे प्लेयर्स के नेतृत्व में भारतीय स्टार्टअप्स ने 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया। इंक42 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 17,000 से ज्यादा लोग पहले ही अपनी नौकरीयां छो चुके हैं और यह लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेरचैट ने रणनीतिक पुनर्गठन के तहत 200 कर्मचारियों या अपने कार्यक्रम के लगभग 15 प्रतिशत को नौकरी से निकाल दिया है। गैगम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लोकों ने अपने कर्मचारियों की कुल संख्या 110 में से लगभग 36 प्रतिशत या 40 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। गूगल समर्थित एडटेक प्लेसफॉर्म अड्डा247 ने विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 250-300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। एनट्रेकर ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा, दिसंबर 2021 में कंपनी द्वारा लगभग 20 मिलियन डॉलर में अधिग्रहित यूपीएससी-केंद्रित एडटेक प्लेटफॉर्म स्टडीआईव्यू से लगभग 100 से 150 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था।



एनएसई और बीएसई ने टाटा मोटर्स के शेयर की डीलिटिंग को दी मंजूरी

मुंबई । बीएसई और एनएसई ने टाटा मोटर्स के शेयरों को (डीवीआर या डिफरेंशियल वेंटिंग राइट्स) को रद्द करने और ऑर्डिनरी शेयर को अलॉटमेंट करने को मंजूरी दे दी है। एक्सचेंजों ने कंपनी शेयरधारकों और ऋणदाताओं के बीच इसके लिए व्यवस्था की योजना को भी मंजूरी दे दी। डीवीआर शेयर पर शेयरधारकों को टाटा मोटर्स के 7 शेयर मिलेंगे। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि टाटा मोटर्स डीवीआर को खत्म कर रही है। कंपनी डीवीआर शेयर को ऑर्डिनरी शेयरों में बदलेगी। टाटा मोटर्स डीवीआर गुरुवार को 1 फीसदी बढ़कर 474 रुपये के भाव पर बंद हुआ था। बता दें कि इसका शेयर एक साल में 100 फीसदी बढ़ा है। डीवीआर शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिस पर वोटिंग और डिविडेंड के लिए विशेष अधिकार जुड़े होते हैं। दरअसल आम नियमों के अनुसार किसी कंपनी के हर स्टॉकहोल्डर को समान वोटिंग राइट्स और डिविडेंड राइट्स मिले होते हैं। ऐसे शेयरों को सामान्य या ऑर्डिनरी शेयर कहा जाता है। इस बीच डीवीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें कंपनियां कुछ ऐसे शेयर जारी करती हैं जिसमें वोटिंग राइट्स आम शेयरों के मुकाबले कम होता है। इसके बदले में कंपनियां डीवीआर के निवेशकों को आम शेयरधारकों के मुकाबले ज्यादा डिविडेंड ऑफर करती है।



एलआईसी के शेयर 7 फीसदी की तेजी के साथ 820.05 रुपए पर पहुंचे

मुंबई ।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयरों में शुक्रवार को जोरदार तेजी आई है। एलआईसी के शेयर 7 फीसदी की तेजी के साथ 820.05 रुपए पर पहुंच गए हैं। एलआईसी के शेयरों का यह 52 हफ्ते का नया उच्च स्तर है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 764.55 रुपए पर बंद हुए थे। बीमा कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल सरकारी की तरफ से बड़ी रियायत दिए जाने के बाद आया है। एलआईसी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। एलआईसी ने बताया है कि सरकार ने 25 फीसदी मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) नॉर्सि पूरा करने के लिए वन-टाइम एग्जेंप्शन दे दिया है। अब

बीमा कंपनी लिस्टिंग की तारीख से 10 साल के भीतर मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को पूरा कर सकती है। बाजार नियामक सेबी के नॉर्सि के मुताबिक किसी भी कंपनी को लिस्टिंग के 3 साल के भीतर या विलय या एक्विजिशन के एक साल के भीतर 25 फीसदी मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्सि को पूरा करना होता है। सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी के आईपीओ का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए था। आईपीओ में कंपनी के शेयर 949 रुपए पर अलॉट हुए थे। कंपनी के शेयर 17 मई 2022 को 867.20 रुपए पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए थे। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट 872 रुपए पर लिस्ट हुए थे। बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर अब भी अपने इश्यू प्राइस से डिस्काउंट पर ट्रेड



कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में एलआईसी के शेयरों में करीब 35 फीसदी का उछाल आया है। बीमा कंपनी के शेयर 26 अक्टूबर 2023 को 604.95 रुपए पर थे। कंपनी के शेयर 22 दिसंबर 2023 को 820.05 रुपए पर पहुंच गए हैं। एलआईसी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 530.20 रुपए है।

अगले सप्ताह पांच दिन बंद रहेंगे बैंक

नई दिल्ली । आने वाले सप्ताह में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों की वजह से बैंक पांच दिन बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छुट्टियों की लिस्ट भी जारी है। इस लिस्ट के अनुसार 25 और 26 दिसंबर को क्रिसमस की वजह से अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। नानालैंड में 27 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है। शनिवार 30 दिसंबर को मेघालय में बैंक बंद रहेंगे, जबकि 31 दिसंबर को रविवार का अवकाश रहेगा। आरबीआई द्वारा घोषित अवकाश अलग-अलग राज्यों में पड़ने वाले त्योहारों और होने वाले आयोजनों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।



शेयर बाजार तेजी के साथ बंद सेंसेक्स 242, निफ्टी 94 अंक ऊपर आया

मुंबई ।

मुम्बई शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिश्रित संकेतों के बाद भी लिवाली हावी रहने से आया है। आज कारोबार के दौरान शेयर बाजार लाभ के साथ ही ऊपर आये। आज के कारोबार में बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक भी 0.74 फीसदी और 1 फीसदी की बढ़त के साथ ही बेंचमार्क से आगे निकल गए। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 241.86 अंक करीब 0.34 फीसदी बढ़कर 71,106.96 अंक पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स में 70,713.56 और 71,259.55 में कामकाज करता रहा। वहीं दूसरी ओर पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 94.35 अंक तकरीबन 0.44 फीसदी ऊपर आकर बंद हुआ। निफ्टी दिन के अंत में 21,349.40 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 21,232.45 और 21,390.50 के बीच कारोबार हुआ।



गत दिवस अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए क्योंकि आर्थिक आंकड़ों से यह आशा

जगी कि फेडरल रिजर्व मौद्रिक नीति में राहत दे सकता है। नैस्टेक 1.3 फीसदी उछला, एस&एंडपी 500 1 फीसदी चढ़ा और डॉव जोन्स 0.9 फीसदी बढ़ा। वहीं एशिया के बाजारों ने हल्की बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। निक्केई, हैंग सेंग और कोस्पी लगभग 0.2 प्रतिशत ऊपर थे। इससे पहले आज सुबह वैश्विक बाजार से मिलेजुले संकेतों के बीच ही घरेलू शेयर बाजार की सपाट स्तर पर शुरुआत हुई। बाजार के प्रमुख इंडेक्स स्थिर पर बने रहे। बीएसई सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ 70,870 पर

एयरटेल, इंटेल्स्मार्ट ने दो करोड़ स्मार्ट मीटर आईओटी से जोड़ने समझौता किया

नई दिल्ली । भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने दो करोड़ स्मार्ट मीटर को इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) से जोड़ने के लिए इंटेल्स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना का क्रियाव्ययन अगले 10 साल में पूरा होने का अनुमान है। एयरटेल ने कहा कि यह क्लाउड और एनालिटिक्स के साथ-साथ हेड एंड सिस्टम जैसे स्मार्ट मीटरिंग अनुप्रयोगों में एयरटेल के प्रवेश का प्रतीक है। यह देश में स्मार्ट मीटरिंग क्षेत्र में सबसे बड़े सौदों में से एक है और यह सभी क्षेत्रों में एयरटेल की तेजी से बढ़ती आईओटी तैनाती में महत्वपूर्ण योगदान देगा। एयरटेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईओटी एयरटेल कारोबार के लिए सबसे तेजी से बढ़ता कारोबारी खंड है। अब हम रणनीतिक रूप से सरकार के 25 करोड़ परंपरागत मीटर को डिजिटल करने के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।



बुजभूषण सिंह के घर लगे पोस्टर- दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा



नई दिल्ली। यौन शोषण के आरोपों के बाद विवादों में आए भाजपा नेता बुजभूषण शरण सिंह के खामखंड संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने स्वर्ण पदक विजेता अनिता शर्याण को हराया है। यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय को 40 जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी और राष्ट्रमंडल खेलां की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अनिता शर्याण को सिर्फ सात मत मिले। शानदार जीत के बाद बुजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की तो वहीं अब बुजभूषण शरण सिंह के बाहर लगे पोस्टर में लिखा है- दबदबा तो है दबदबा तो रहेगा। ये तो भगवान ने दे रखा है। संजय ने चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'यह देश के हजारों पहलवानों की जीत है जिन्हें पिछले सात से आठ महीनों में नुकसान उठाना पड़ा है।' अनिता का पैनाल हालांकि महासंघ पर अपने नाम करने में सफल रहा जय प्रेम चंद लोचब ने दर्शन लाल को हराया। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के पूर्व सचिव लोचब ने 27-19 से जीत दर्ज की। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 'फुड ज्वाइंट्स की चेन' चलाने वाले और प्रदर्शनकारी पहलवानों के करीबी माने जाने वाले देवेंद्र सिंह कादियान ने आईडी नानावटी को 32-15 से हराकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। संजय सिंह मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले हैं। इस समय वो वाराणसी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। संजय सिंह बल्लू पिछले डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय से कुश्ती संघ से जुड़े हैं और बुजभूषण शरण सिंह के काफी नजदीकी माने जाते हैं। वो 2008 से ही वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष हैं। संजय सिंह बल्लू का 2009 में प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चयन हुआ था। अनिता शर्याण को बुजभूषण शरण सिंह का विरोधी माना जाता है। वह हरियाणा के पिबानी जिले की रहने वाली हैं। अनिता ने पहलवानों के यौन उपीड़न मामले में भी बुजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी गवाही दी थी। अनिता कुश्ती के मैदान में भी बड़ी सफलता हासिल कर चुकी हैं, उन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। अगर अनिता शर्याण ये चुनाव जीततीं, तो वो पहली महिला पहलवान होती।

क्रिसमस और नए साल पर देर रात तक खुली रहेगी शराब की दुकान

मुंबई। शराब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है. महाराष्ट्र सरकार ने क्रिसमस और नए साल पर मुंबई में होटल, बार और पब को देर रात तक खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार ने ये इजाजत तीन दिनों के लिए दी है. इसके मुताबिक, इस महीने 24, 25 और 31 दिसंबर को शराब की खुदरा दुकानें रात 10.30 बजे से 1 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. इस संबंध में एसाईज विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया है. इस सर्कुलर में लिखा है कि, महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 139 (1) (सी) और धारा 143 (2) (एच 1) (आईवी) के तहत क्रिसमस एवं नव वर्ष के अवसर दिनांक 24 और 25 दिसंबर एवं दिनांक 31 दिसंबर को सरकार द्वारा विभिन्न शराब बिक्री लाइसेंस निर्धारित समय के बाद देर रात तक खुले रखने की मंजूरी दी जा रही है। वलब अगले दिन सुबह 5 बजे तक और पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के लिए रात 1.30 बजे से सुबह 5 बजे तक। साथ ही बीयर बार को रात 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जारी रखने की इजाजत दी गई है. इसके अलावा, महानगरपालिका के साथ-साथ अ, व और ब वर्ग के नगरपालिका क्षेत्र में लाइसेंसधारियों के लिए बार और वाइन की दुकानों को रात 11 बजे से रात 1 बजे तक और अन्य स्थानों पर रात 10 बजे से रात 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

कोविड-19 के बाद वैश्विक कर्ज में वृद्धि चिंता का विषय

नई दिल्ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 के बाद वैश्विक कर्ज में वृद्धि एक बड़ी चिंता का विषय है। यह 2022 में 92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 92 प्रतिशत है। 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक सार्वजनिक ऋण का लगभग 20 प्रतिशत ऋण जमा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक ऋण साल 2028 तक 132 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के विभिन्न ऋण चक्रों के विश्लेषण से पता चलता है कि कोविड के बाद ऋण के स्तर में तेजी से वृद्धि के कारण ऋण संकट में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे कम आय वाले देशों में डिफाल्ट होने का जोखिम बढ़ गया है। एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि महामारी के बाद एडवांस्ड और डेवेलपिंग में ऋण स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं लो इंटरनेट रेट का फायदा उठा रही हैं। लेकिन अब, ब्याज दरें लंबी अवधि तक ऊंची रहने के साथ, उन्हें बढ़ती लागत पैदा लागत का दर्द महसूस होगा। रेटिंग एजेंसी की मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, वैश्विक ऋण में हालिया उछाल इसकी तेज वृद्धि और भारी मात्रा दोनों में उल्लेखनीय है। ऋण के स्तर में तेज वृद्धि के साथ, ऋण संकट की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। 2020 के बाद से लगभग 19 अर्थव्यवस्थाएं या तब अपने ऋण दायित्वों पर डिफॉल्ट कर चुकी हैं या उसका पुनर्गठन किया है।

आप नेता संजय सिंह को झटका, नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की राजन एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मुनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने राज्यसभा सांसद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले गुरुवार को अदालत ने सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला 22 दिसंबर के लिए तय करते हुए कार्यवाही स्थगित कर दी थी। दलीलों के दौरान, सिंह के वकील ने कथित रिश्त के संबंध में, विशेष रूप से आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास की ओर इशारा किया। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह के आवेदन का विरोध किया और दावा किया कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो इसमें संभावित हस्तक्षेप हो सकता है। 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आप सांसद सिंह ने 2021-2022 की रद की गई आबकारी नीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के ईडी के दावे का खंडन किया, उन्होंने आरोप लगाया कि इसने वित्तीय लाभ के लिए विशिष्ट शराब संस्थाओं को लाभ पहुंचाया। वह किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं। दिल्ली शराब घोटाला, या उत्पाद शुल्क नीति मामला, इन आरोपों के र्द-गिर्द घूमता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया, जिससे विशिष्ट डीलरों को फायदा हुआ, जिन्होंने कथित तौर पर रिश्त दी थी। पिछले साल, ईडी ने मामले में अपना पहला आरोप पत्र दाखल किया था, जिसमें 200 से अधिक खोज अभियानों का खुलासा किया गया था। मुख्य सचिव की जुलाई की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अनुशंसित सीबीआई मामले के आधार पर एफआईआर शुरू की गई थी।

फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़े गए ईरानी को दो साल की जेल

महाराजगंज। महाराजगंज की एक अदालत ने फर्जी पासपोर्ट पर नेपाल जाने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किए ईरानी नागरिक को दो साल की सजा दी है। एडीजीसी ने शुक्रवार को बताया कि न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को आरोपी ईरानी नागरिक 38 वर्षीय हुसैन हमीदिया को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है।

स्मृति ईरानी ने लगाया गांधी परिवार पर अमेठी के किसानों को लूटने का आरोप

600 रुपये में किराए पर ली 30 एकड़ जमीन,

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी को हराने तक पूर्व पारिवारिक गृह रहे अमेठी में जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ 600 रुपये में 30 एकड़ जमीन किराए पर ली। एनआई की स्मिता प्रकाश के साथ उनके पॉडकास्ट पर बातचीत में अमेठी से भाजपा के लोकसभा सांसद ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने औद्योगिकरण के नाम पर किसानों और अन्य लोगों से जमीन हथिया ली। मुझे लोगों को यह बताने में थोड़ा समय लगा कि वास्तव में मुझे पर विश्वास करें कि गांधी परिवार द्वारा लोगों से उनकी जमीनें लूटी जा रही थीं। मैंने संसद में यह कहा है।

600 रुपये में 30 एकड़ जमीन किराए पर ली गई। परिवार (गांधी) वहां अपने लिए एक अच्छा, सुंदर कॉम्प्लेक्स बनाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रो ने आगे आरोप लगाया कि जमीन का एक टुकड़ा, जिसका

उपयोग अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए किया जाना था, गांधी परिवार ने एक कार्यालय के लिए हड़प लिया। ईरानी ने दावा किया कि जो लड़कियां परिवार (गांधी) के खिलाफ गईं और उनके खिलाफ घटना दिया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। 2014 के आम चुनाव में स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी से हार गईं। उन्होंने 2019 में गांधी से सीट छीनकर उस हार का बदला लिया। 47 वर्षीय ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की सबसे युवा सदस्य हैं।

पॉडकास्ट के दौरान, स्मृति ईरानी ने अपने प्रारंभिक जीवन पर भी प्रकाश डाला और बताया कि कैसे उन्होंने टाटा छात्रवृत्ति हासिल की। आप जो कुछ भी करते हैं उसका श्रेय पिताजी को जाता है- और अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए मुंबई जाने की इच्छुक थीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर कुछ बनना चाहती थी।



सदन कार्यवाही: पुलिस को दी न्यायाधीश, जूरी और एक्जिक्यूटिव शक्तियां: ओवैसी

-आईपीसी की जगह तीन नए कानून पर चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लिए गए तीन नए कानूनों पर बहस चल रही है। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इन तीनों कानूनों को गुलामी की निशानी को मितने का प्रयास बताया। ए आईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इन नए कानूनों की तुलना रौलेट एक्ट से कर दी। बहस के दौरान ओवैसी ने शायराणा अंदाज में कहा, हमको शाहों की अदालत से तबक़ो तो नहीं, आम कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। इसके साथ ही 20 दिसंबर को लोकसभा में उन्होंने जॉन एलिया साहब का शेर-जुम में हम कमी करें भी तो क्या, तुम सजा भी तो कम नहीं करते, पढ़ा।

ओवैसी के अनुसार मोदी सरकार द्वारा लिए गए इन तीनों ही विधेयक में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो काफी खतरनाक हैं। ये देश के आम नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा है। इन नए कानूनों पर ओवैसी कहते हैं कि ये विधेयक भारत के आम लोगों के खिलाफ हैं। इसमें पुलिस को न्यायाधीश, जूरी और एक्जिक्यूटिव के रूप में काम करने की शक्तियां दे दी गई हैं। अगर इसे कानून की शकल दी जाती है तो आम लोगों से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे।

आईपीसी में फिलहाल 511 धाराएं हैं। इसकी जगह भारतीय न्यायिक संहिता लेता है तो इसमें 356 धाराएं रह जाएंगी। पुराने कानून से नए कानून में 175



धाराएं बदल जाएंगी। भारतीय न्यायिक संहिता में 8 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं हटाई जाएंगी।

इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं रह जाएंगी और 160 धाराएं बदल जाएंगी। नए कानून में 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 खत्म का गई है। ओवैसी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि देश की वर्तमान सरकार का मंत्र जनता के लिए अविश्वास और धंधे के लिए विश्वास मंत्र है। हमारे देश में आज सूट पहनने वाला व्यक्ति किसी भी सजा से बच जाता है। खाकी पहना व्यक्ति किसी को भी गोली मार सकता है उन्हें किसी तरह का जवाब भी नहीं देना होता। लेकिन, संसद में बैठे जिन लोगों पर आतंकवाद के आरोप हैं, वह इस कानून में बताएंगे कि आतंकवाद क्या है।

अपने पूरे भाषण के दौरान गुस्से में नजर आ रहे ओवैसी को जब किसी अन्य सदस्य ने टोका तो उन्होंने कहा कि वह मरने को तैयार हैं, उनकी गोलियां खत्म हो

जाएंगी लेकिन वह जहां रहेंगे। ओवैसी ने इसी दौरान साल 1999 में उनके साथ ही पुलिस के हाथों पिटाई का भी एक किस्सा साझा किया। ओवैसी कहते हैं कि, 22 दिसंबर 1999 को पुलिस ने मुझे पीटा था उस दिन मेरे सिर पर 20 टांके लगाए गए थे। उस वक टीडीपी की सरकार थी और मुझे पीटने वाले दोनो पुलिसवालों को आईपीएस बना दिया गया।

गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक का रस्ता लोकसभा में साफ हो गया। अब इन तीनों बिलों को जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। इसके बाद इन्हें लोकसभा और बाद में राज्यसभा में पारित कराया जाएगा। अगर यह तीन विधेयक कानून की शकल लेता है तो ये बिल भारतीय दंड संहिता (आपीसी), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले लेंगे।

2019 के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को पटना हाईकोर्ट से राहत....मामला हुआ रद्द

चंडीगढ़। पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर 2019 के लोकसभा चुनाव में धर्म के आधार पर वोट की अपील करने के मामले में धर्म एफआईआर को पटना हाईकोर्ट ने रद्द करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई कर पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेता सिद्धू ने तब अपने भाषण के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मुस्लिम वोटों के बटवारे के खिलाफ आगाह किया था, सिद्धू की मंशा सांप्रदायिक सद्भाव विगाड़ने की नहीं बल्कि मुस्लिम वोट के बटवारे को रोकने की थी। सिद्धू के खिलाफ 16 अप्रैल, 2019 में आईपीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। निचली अदालत के फैसले को सिद्धू ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि सिद्धू के भाषण से ऐसा नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता ने दो वर्गों के लोगों या दो धर्मों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया। सिद्धू ने केवल इतना कहा कि ओवैसी मुस्लिम वोटों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धू के बयान में किसी भी सांप्रदायिक तनाव या हिंसा का जिक्र नहीं है, बल्कि केवल मुस्लिम समुदाय को ओवैसी के इशारे पर अपने वोट विभाजित करने के बारे में आगाह किया गया है। हाईकोर्ट ने आरोपों को खारिज किया कि सिद्धू ने धर्म के नाम पर वोट मांगे थे।

सीएम विष्णुदेव का मंत्रिमंडल गठित, 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ



-केन्द्र की मोदी सरकार ने नए कानून के तहत किया सजा का प्रावधान

रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नए मंत्रिमंडल का गठन आज शुक्रवार को कर दिया गया। 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है।

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने और मुख्यमंत्री विष्णुदेव के बनने के बाद ही आज शुक्रवार को मंत्रिमंडल का गठन भी कर दिया गया। इसमें 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। मंत्रिमंडल की शपथ लेने वाले विधायकों में बुजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल और लखन लाल देवांगन भी शामिल हैं। बलौदाबाजार के विधायक विधायक टंकमर वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्री बने टंकमर वर्मा शिक्षक को नौकरी छोड़



मर्दानी 3 में काम करेंगी रानी मुखर्जी!

बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री रानी मुखर्जी फिल्म मर्दानी में काम करती नजर आ सकती है। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी वर्ष 2014 में प्रदर्शित हुयी। रानी मुखर्जी ने मर्दानी में एक सशक्त पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय की भूमिका निभाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। मर्दानी की सफलता के बाद वर्ष 2019 में मर्दानी 2 बनायी गयी। चर्चा है कि अब मर्दानी 3 बनायी जा रही है। रानी मुखर्जी ने कहा, एक अभिनेत्री के रूप में मैं हमेशा मानती हूँ कि हम कोई फिल्म इसलिए नहीं करना चाहते, क्योंकि वह अच्छी लगती है। हमें तब फिल्म करना चाहिए जब स्क्रिप्ट अच्छी हो और जब हम ऐसी फिल्म बनाना चाहते हों जो बदलाव ला रही हो। यदि कहानी में वह दम नहीं है तो हम मर्दानी 3 नहीं बना सकते हैं। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आज जुड़ें, लड़कियों को यह सशक्त लगे। तभी हम मर्दानी 3 बना सकते हैं। इसे सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए

व्यक्ति, यह रोमांचक लगता है। रानी मुखर्जी ने बताया कि मर्दानी फेंचाइज की फिल्म केवल दर्शकों के प्यार की वजह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि महिला प्रधान फेंचाइज फिल्म का चलना बहुत कठिन होता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए दर्शकों का प्यार चाहिए। जहां तक मर्दानी 3 की बात है, तो मैं खुद वापस आना चाहती हूँ। हर फिल्म को एक अच्छी कहानी की तलाश होती है। मर्दानी 3 फिल्म भी ऐसी है, जिसे बनाया जाना चाहिए। लेकिन बिना अच्छी स्क्रिप्ट के इसका तीसरा पार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में हम अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में हैं। जैसी ही हमें अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, हम मर्दानी 3 पर तुरंत काम शुरू कर देंगे। फेंचाइज फिल्म हो या फिर दूसरी कोई नई फिल्म, हर फिल्म में आपका नाम जुड़ा होता है, आप उसमें होते हैं, तो आपसे दर्शकों की एक उम्मीद जुड़ जाती है। उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना होता है। कलाकार की जिम्मेदारी हर फिल्म की ओर बनती है।

अवॉर्ड्स के मंच पर ऋतिक का दिखेगा जलवा

इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवॉर्ड्स (आईटीए) कलाकारों की अलग-अलग कलाकारी और मनोरंजन उपलब्धियों को सम्मान देते हैं। इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवॉर्ड्स इंडस्ट्री में सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यहां इस साल टेलीविजन, ओटीटी और फिल्म प्लेटफार्मों पर निर्मित बेस्ट काम को सम्मानित किया जाएगा। राठौड़, सायली सालुंखे, विशाल आदित्य सिंह, शालीन भनोट, भाविका शर्मा, शक्ति अरोड़ा, विजयेंद्र कुमरिया, हिमांशी पाराशर, सायली सालुंखे, नवनीत मलिक, खुशी दुबे के साथ कई बॉलीवुड स्टार्स जिनमें ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, भूमि पेडनेकर, विजय वर्मा, शोभिता धूलिपाला और कई अन्य हस्तियां स्पॉट हुईं। 23वां भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार स्टार प्लस पर प्रसारित होने के लिए तैयार है, इसकी भव्यता देखने के लिए तैयार हो जाइए। बता दें कि तेइसवें इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवॉर्ड्स का रेड कार्पेट 10 दिसंबर, 2023 को आयोजित किया गया था। इसके रेड कार्पेट पर मनोरंजन जगत के सितारों की महफिल सजी थी।



हैली बीबर का जबर्दस्त है बॉल्ड लुक

एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरों सामने आई हैं जो इस समय चर्चा में हैं। दरअसल, ये तस्वीरें उस समय विलक की गई जब हैली वेस्ट हॉलीवुड में बोस्ट्रेगा वेनेटा में क्रिसमस की शापिंग के लिए निकली थीं। इन तस्वीरों में हैली का बॉल्ड लुक देखने को मिल रहा है। लुक की बात करें तो हैली लाइट ब्राउन स्वेटर और ब्लैक मिनी स्कर्ट में हॉट लग रही हैं। मिनी स्कर्ट में हैली अपनी टोन्ड लेग्स प्लान्ट कर रही हैं। हैली ने ब्लैक कैप, शोडस से अपने लुक को पूरा किया। फैंस उनकी इन तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं। काम की बात करें तो हैली बीबर को आखिरी बार टीवी सीरीज डेव में देखा गया था, जिसमें उनके किरदार को खूब पसंद किया गया था। बता दें कि हॉलीवुड मॉडल एंड एक्ट्रेस हैली बीबर अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों के चलते चर्चा में रहते हैं। वह अक्सर फैंस के साथ अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।



मुन्नाभाई एमबीबीएस के 20 साल पूरे

प्रतिष्ठित फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस पर अभिनेता अरशद वारसी जश्न मना रहे हैं। अरशद ने हाल की एक घटना शेयर की, जब उन्होंने और संजय दत्त ने एक प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग की, जहां वह मुन्ना भाई और सर्किट के कॉस्ट्यूम पहनकर गए। अरशद का सर्किट किरदार पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रिय बन गया है और यह दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण स्थापित करता है। मुन्ना के साथ उनकी जबर्दस्त केमिस्ट्री है। लगे रहो मुन्ना भाई में जब मुन्ना और सर्किट के बीच गलतफहमी हो जाती है तो एक खालीपन महसूस होता है और वह दृश्य जहां मुन्ना सर्किट से सौरी कहता है, हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते

हैं। पुरानी यादों के रास्ते पर चलते हुए अरशद ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दो दशक हो गए हैं। सर्किट मेरे लिए एक बहुत ही खास किरदार है, यह मेरे दिल के बहुत करीब है। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर मुन्नाभाई एमबीबीएस की एक तस्वीर भी शेयर की और कैप्शन में लिखा, 20 साल, वाह, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, मुन्ना और सर्किट को इतना प्यार करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।



बिसलरी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसेडर बनी दीपिका पादुकोण

मिनरल वाटर ब्रांड बिसलरी ने नये कैम्पेन बिसलरी मडिकअपमें दीपिका पादुकोण को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसेडर बनाया है। विज्ञापन फिल्म में दीपिका मशहूर गाने 'झूम झूम झूम बाबा' पर नये अंदाज में थिरकती नजर आयेंगी। इस दौरान वह ताजगी पाने के लिये 'पानी पीती दिखाई देंगी'। दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसेडर बनाने पर अपनी बात रखते हुए, बिसलरी इंटरनेशनल प्रा. लि. की वाइस चेयरपर्सन जयंती चौहान ने कहा, हमारा नया कैम्पेन बिसलरी मडिकअप पहली बार दीपिका पादुकोण के मशहूर अंदाज में मजा और रोमांच लेकर आ रहा है। हम दीपिका पादुकोण को अपनी पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसेडर बनाकर उत्साहित हैं। उनका काम और वैल्यूज हमारी ब्राण्ड फिलोसॉफी से मेल खाते हैं। उनके साथ हम अपने ब्राण्ड की नये जमाने में तरक्की दिखा सकते हैं। हमें विश्वास है कि यह कैम्पेन सभी को पसंद आएगा और लोग बिसलरी के साथ अपनी प्यास बुझाने का मजा लेंगे। दीपिका पादुकोण ने बिसलरी की ग्लोबल एम्बेसेडर बनने पर अपना उत्साह दिखाते हुए कहा, 'मैं बिसलरी जैसे मशहूर ब्रांड के साथ जुड़कर बहुत खुश हूँ। बिसलरी इंटरनेशनल प्रा. लि. के मार्केटिंग हेड तुषार मल्होत्रा ने कहा, 'बिसलरी मडिकअपकेम्पेन हमारे ब्रांड को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ब्राण्ड के प्रति लोगों का प्यार बढ़ेगा और हमारे उपभोक्ता रोमांचक चर्चाओं में शामिल होंगे। बिसलरी मडिकअपकेम्पेन को निर्वाणा फिल्मस ने शूट किया है और इसका निर्देशन प्रकाश वर्मा ने किया है।



प्रभास स्टार फिल्म 'सालार' का होगा राउण्ड द क्लाक प्रदर्शन

शाहरुख खान की 'डंकी' को भारी टक्कर देने के लिए 22 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली प्रभास स्टार फिल्म 'सालार' को लेकर फैंस उत्सुक हैं। ये फिल्म हिंदी समेत तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगू भाषा में रिलीज होने वाली है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही 23 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर लिया है। तेलंगाना में फिल्म का अलग क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसके बाद वहां की सरकार ने 'सालार' के देर रात और तड़के सुबह के शो रखने की इजाजत दे दी है। तेलंगाना में प्रभास की 'सालार' के शो सुबह 4 बजे शुरू होंगे और आखिरी शो देर रात 1 बजे का होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने फिल्ममेकर्स को इसकी टिकट फीस बढ़ाने को भी कहा है। सुत्रों के मुताबिक तेलंगाना सरकार ने एक बयान जारी किया है। जिसमें सरकार की ओर से कहा गया है, सरकार ने मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, तेलंगाना राज्य में 'सालार' फिल्म के लिए 22 दिसंबर 2023 को सुबह 4 बजे छठे शो की अनुमति दी और सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स के लिए दरों में 65 रुपये और 100 रुपये की बढ़ोतरी की अनुमति दी। 'डंकी' और 'सालार' की टक्कर केवल बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, एडवांस बुकिंग के मामले में भी रही। 'डंकी' ने 1,44,830 टिकट बेचकर 4.46 करोड़ कमाये और 'सालार' के 1,54,705 टिकट विक्रे और फिल्म ने 3.58 का कलेक्शन किया। शाहरुख खान की फिल्म की तुलना में प्रभास स्टार ने 8,875 ज्यादा टिकट बेचे हैं, लेकिन टिकट सस्ते होने के कारण फिल्म का एडवांस कलेक्शन 'डंकी' से कम है।

श्रीमद रामायण में 'हनुमान' की भूमिका निभाकर गौरान्वित हैं निर्भय वाधवा

जानेमाने अभिनेता निर्भय वाधवा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले सीरियल श्रीमद रामायण में 'महाबली हनुमान' की भूमिका निभाकर गौरान्वित हैं। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन दर्शकों के लिए लेकर 'श्रीमद रामायण' लेकर आ रहा है, जिसका प्रीमियर 01 जनवरी, 2024 को होगा और यह हर सोमवार से शुरुवार रात 09 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा। सीरियल 'संकट मोचन महाबली हनुमान' समेत कई सीरियल में हनुमान की भूमिका निभा चुके निर्भय वाधवा एक बार फिर 'श्रीमद रामायण' में हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। निर्भय वाधवा ने कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे महाबली हनुमान की भूमिका निभाने का मौका मिला है। भगवान हनुमान के साथ मेरा दिव्य संबंध है, और मैं इस जीवन से भी बड़ी भूमिका को फिर से निभाने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। महाबली हनुमान, भगवान राम के सबसे महान भक्त हैं और यह भक्ति उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं सोनी टीवी और स्वस्तिक प्रोडक्शन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 'श्रीमद रामायण' में महाबली हनुमान का किरदार निभाने का अवसर दिया। मैं विशेष तौर पर इसके लिये स्वस्तिक प्रोडक्शंस के संस्थापक और श्रीमद रामायण के निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो दर्शकों के लिये इतना बड़ा शो लेकर आये। श्रीमद रामायण मेरे करियर का सबसे बड़ा शो होगा। हनुमान जी की भूमिका निभाकर मैं गौरान्वित हूँ। निर्भय वाधवा ने कहा, जब आप हनुमान जी किरदार निभाते हैं, उनका गेटअप धारण करते हैं तो आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आप पॉजिटिव हो जाते हैं। कहते हैं कि जय श्री राम बोलने से सारी तकलीफ दूर हो जाती है। यह सच है, मैंने अपने लाइफ में ये सब चीजें महसूस की हैं। श्रीमद रामायण में काफी डिटेल के साथ काम किया गया है। श्रीमद रामायण युवाओं को बेहद पसंद आयेगी। श्रीमद रामायण देखने के बाद लोगो में बड़ो का आदर करने की भावना अंदर आयेगी। यह शो सिखाएगा कि बड़ो का सम्मान कैसे करें। श्रीमद रामायण में हनुमान जी के किरदार में हर बारीक से बारीक पहलुओं का ध्यान रखा गया है। इस किरदार को फिर से निभाना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा।

